संसद में बहस

vke ctV 2009&10

‘आम बजट’ में ‘आम आदमी’ गायब

- Mk- eqjyh euksgj tks'kh
- Jh jktukFk flag
- Jh ,e- oSadS;k uk;Mw
- Jh v#.k 'kkSjh
- Jh ,u-ds- flag

Hkkjrh; turk ikVhZ

प्रकाशकीय

संप्रग सरकार के केन्द्रीय वित्त मंत्री ने संसद में 6 जुलाई को वर्ष 2009–10 के लिए ‘आम बजट’ प्रस्तुत किया। प्रमुख विपक्षी दल के नाते भाजपा सांसदों ने तथ्य और तर्क के बूते केन्द्र सरकार की गलत नीतियों पर जमकर प्रहार करते हुए बजट को दिशाहीन एवं निराशाजनक करार दिया।

बजट पर लोकसभा में चर्चा आरंभ करते हुए भाजपा सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने आशंका व्यक्त की कि बजट में 9 प्रतिशत विकास दर और चार प्रतिशत कृषि विकास दर हासिल करने का लक्ष्य अति महत्वाकांक्षी है जबकि इसे अमल में लाने की गंभीरता और दिशा का सख्त अभाव है। कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद श्री राजनाथ सिंह ने कृषि, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण से जुड़े ज्वलंत प्रश्नों पर विस्तार अपने विचार रखे।

राज्यसभा में चर्चा की शुरूआत करते हुए भाजपा सांसद श्री वेंकैया नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी पर बजट में आंकड़ों की बाजीगरी करने का आरोप मढ़ा। उन्होंने कहा कि बजट में मूल्य वृद्धि, आर्थिक मंदी, कृषि और आंतरिक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। भाजपा सांसद श्री अरुण शौरी ने संप्रग सरकार की तथाकथित उपलब्धियों की पोल खोलते हुए कहा कि सरकार केवल संकल्प पारित करती है व ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करती है। वास्तविक समस्या पर ध्यान नहीं देती।

इस बार हम जाने–माने अर्थशास्त्री व जद(यू) सांसद श्री एन. के. सिंह का राज्यसभा में आम बजट पर दिया गया भाषण भी प्रकाशित कर रहे हैं। श्री सिंह ने संप्रग सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि सकल राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 12–13 प्रतिशत बैठेगा। जिसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का गहन दबाव बढ़ेगा।

हम इस पुस्तिका में भाजपा सांसद डा. मुरली मनोहर जोशी, श्री वेंकैया नायडू, श्री अरुण शौरी एवं जद(यू) सांसद श्री एन. के. सिंह का भाषण प्रकाशित कर रहे हैं ताकि देश की आम जनता संप्रग सरकार के खोखले दावों की असलियत जान सके।

çdk'kd
Hkkjrh; turk ikVhZ
11] v'kksd jksM]
ubZ fnYyh&110001

tqykbZ] 2009

लोकसभा

अमल में लाने की गंभीरता और दिशा का सख्त अभाव

& Mk- eqjyh euksgj tks'kh

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस सरकार की दूसरी पारी के पहले बजट के बारे में अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है और समय दिया है। मेरे सामने माननीय वित्त मंत्री जी विराजमान हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण में कुछ ऐसे लक्ष्य रखे हैं जो यदि पूरे हो जाएं, तो सारे देश को बहुत प्रसन्नता होगी और मैं प्रभु से यह कामना करता हूं कि उन्हें शक्ति दे कि वह इन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो सकें। मुझे यह आशंका है कि जितने महान लक्ष्य उन्होंने रखे हैं, वे पूरे हो सकेंगे या नहीं।

महोदय, बजट भाषण में लक्ष्य घोषित करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको पूरा करना और उसको पूरा करने के लिए साधन जुटाना और उसके साथ–साथ एक इच्छा शक्ति को प्रकट करना, एक प्रबंधन को सामने लाना, आर्थिक और वित्तीय साधनों को जुटाना, यह बहुत कठिन काम है। आज की परिस्थिति में जो लक्ष्य उन्होंने रखे हैं, उनकी तरफ वे सफलता के साथ बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि देश को बहुत प्रसन्नता होगी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य बनाने के बाद शायद वह अब यह सोचें कि वे कुछ ज्यादा कह गए हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारी किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए, गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, किसानों और खेती को उसकी वास्तविक स्थिति जो इस देश में कभी थी, वहां तक पहुंचाने के लिए जहां कहीं हमारी और हमारे राज्यों की सरकारों की सहायता की जरूरत होगी, हम उसके लिए तैयार हैं।

आपने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि नई सरकार सन् 2009 और 2010 की अपनी जो नीतियां बनाएगी, उनके कुछ विशेष और ऐसे लक्ष्य

होंगे जिन्हें आपने गिनाया है। आपने 8 या 10 लक्ष्य गिनाए हैं। उनमें से एक लक्ष्य है –

"sustain a growth rate of at least 9 per cent per annum over an extended period of time."

इसके साथ–साथ आपने और जो बातें लिखी हैं, उनका एक महत्वपूर्ण पैरा आपको बताता हूं –

"ensure that Indian agriculture continues to grow at an annual rate of 4 per cent."

यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और यदि इसे चार प्रतिशत कंटीन्यू करें, इसे आप इनश्योर करें, अगर आप इस बजट के माध्यम से उसे कर सकें, तो मैं समझता हूं कि आप इस देश में चमत्कार कर देंगे।

मेरे सामने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो अप्रैल, 2008 में छपी। उसमें कहा गया है –

"The slow growth of agriculture has been explicitly noted as a matter of concern in the Approach Paper to the 11th Plan and accelerating the rate of growth of agricultural production is seen as central to a more inclusive growth, if not growth per se."

इनक्लूसिव ग्रोथ आपके इस बजट का एक मुख्य केन्द्र बिन्दु रहा है। आगे चलकर रिपोर्ट कहती है –

"Taking output growth first, we find that even close to four decades since the Green Revolution there is no permanent rise in the rate of growth. Together with the data for cereal, since 1991 we are able to see that it is the slowing of output growth in this decade that depresses the rate of growth from 1967 to 2003. To sum up then, there is an across the board slowing of output and yield growth since 1991 for the two main groups in Indian crop agriculture. For all crops there is slowing of growth in area, production and yield." There is a slowing of growth in area, production and yield. This is very serious.

It further says:

"The period since 1991, that is when the reforms began, now emerges as a kind of watershed in time when growth in Indian agriculture, resurgent from the middle 1960s, was arrested. Concerns of livelihood and food consumption arise naturally from the recent record of agricultural growth."

आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ पर इम्प्लॉयमैंट निर्भर करता है, उस पर देश का सारा आर्थिक विकास निर्भर करता है क्योंकि 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है।

उपाध्यक्ष जी, मेरे सामने एक और तस्वीर है जो बहुत चिन्ताजनक है। वह यह है कि हमारे देश की जनसंख्या जैसे–जैसे बढ़ी है, वैसे–वैसे मैं देख रहा हूं कि हमारा अन्न का उत्पादन घटा है और अन्न उत्पादन के लिए जो कृषि क्षेत्र था, दर्शित क्षेत्र था, वह भी घट गया है। इसके साथ–साथ अन्न की उत्पादकता भी घट गई है यानी प्रति हैक्टेयर जितना उत्पन्न होना चाहिए, उतना उत्पन्न नहीं हो रहा है। हमारे देश में कृषि के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है, वह उपलब्ध नहीं है, वह निरंतर घट रही है। हमारे पास उसके आंकड़े हैं। हमारे पास सन् 1971 में 1,24,316 हजार हैक्टेयर उपलब्ध था और आज यह 1,23,710 हजार हैक्टेयर रह गया है। यह फूडग्रेन्स के अंदर ही घटा है। इसके अतिरिक्त जो भूमि है, जिसमें अन्न के अलावा और चीजें पैदा होती हैं, वह क्षेत्र भी घट गया है। इसी तरह यील्ड घट गई है और फूडग्रेन प्रोडक्शन जो एक बार हमारे देश में 202 किलोग्राम पर कैपिटा, पर ईयर हो गया था, वह फिर से घटकर 191 किलोग्राम पर कैपिटा पर ईयर एवेलेबिलिटी हो गई है।

इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा को छोड़कर बाकी सब जगह अन्न उत्पादन घटा है। केवल पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, जिसमें अन्न उत्पादन अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन बाकी सब जगह घट गया है। बिहार में 134 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से घटकर 91 किलोग्राम रह गया है। इसमें झारखंड भी शामिल है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 254 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हुआ करता था, वह घटकर 210 किलोग्राम रह गया है। इसमें उत्तरांचल भी शामिल है। तमिलनाडु में सिर्फ 104 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का उत्पादन हो रहा है और केरल में केवल 19 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की ऐवेलेबिलिटी है। खेती की यह जो स्थिति है, उसी तरह से अन्न के लिए उपलब्ध भूमि और पैदावार की स्थिति है, यह बहुत चिंताजनक है। आप कहते हैं कि इसे आप चार प्रतिशत तक ले जायेंगे। आप इसे कैसे ले जायेंगे? मैं आपका एलोकेशन देखता हूं, तो इस बार एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज के लिए 10629 करोड़ रुपये है, जो सारे खर्चे का केवल एक प्रतिशत है। आपने जो 10 लाख कुछ हजार करोड़ रुपये रखे हैं, उसका केवल एक प्रतिशत भाग आप कृषि पर

खर्च कर रहे हैं जबकि आपका लक्ष्य उसे चार प्रतिशत तक की ग्रोथ तक ले जाने का है। दूसरी तरफ हम यह देख रहे हैं कि किसानों की आमदनी किस तरह से घट रही है और आज उसकी क्या हालत है? एनएसएसओ के वर्ष 2003–04 में जो आंकड़े थे, उसके तहत किसानों की आमदनी 2115 रुपया प्रति परिवार प्रति मास थी। आजकल घर में काम करने के लिए हमारे जो भाई बहन आते हैं, उनको भी तीन हजार रुपये से कम नहीं मिलता। दिल्ली में तो चार, साढ़े चार रुपये तक मिलते हैं, लेकिन किसानों की आमदनी औसत देश भर में 2115 रुपया प्रति परिवार प्रति मास थी। यह आमदनी प्रति व्यक्ति न होकर प्रति परिवार है।

कल्याण सिंह जी, यू.पी. में यह आमदनी 1630 रुपये प्रति व्यक्ति है। जम्मू–कश्मीर में सबसे अधिक आमदनी 5500 रुपये है। वहां बागवानी की वजह से यह आमदनी ज्यादा है। पंजाब में तीन हजार रुपये है। उसके बाद केरल है। अगर यह स्थिति किसानों की आमदनी की है, अगर यह स्थिति भूमि पर काम करने वाले लोगों की है, तो स्वाभाविक है कि लोग छोड़कर चले जायेंगे और आपका एनएसएसओ 2005 का कहता है कि

"About 41 per cent Indian farmers have expressed their willingness to opt out of the agriculture. In Punjab too nearly 37 per cent farmers expressed their willingness to leave agriculture. About two lakh small and marginal farmers in Punjab have already been pushed away from farming during 1990-2001, according to a recent survey."

अब अगर आप यह स्थिति देखें, तो इसे चार परसेंट ग्रोथ तक ले जाना, वास्तव में आपने बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है। अगर आप इसे पूरा करेंगे, तो देश आपका बहुत गुणगान करेंगे। हम इसमें आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं, मगर हम रास्ता जानना चाहते हैं कि इसे आप कैसे करेंगे? मेरे पास बहुत आंकड़े हैं, जिन्हें पढने़ की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहेंगे, तो मैं दे सकता हूं। वैसे सब आंकड़े आपकी ही सरकार के दिये हुए हैं। हालत यह है कि अभी उस दिन सदन में हमारे एक सम्मानित सदस्य ने बताया था कि चार–पांच हजार किसान इच्छा मृत्यु के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें मरने की इजाजत दे दी जाये।

Janata Dal (United) Legislator from Chhatarpur, Shri Radhakishan Kishore said that failure of the successive Governments to address the issue of water scarcity in the area

which had been declared drought prone by the Centre in 1974 was responsible for this.

आप पानी के लिए क्या करेंगे? कृषि को ठीक करने के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे सामने आपके पुराने वित्त मंत्री माननीय श्री चिदम्बरम जी, उन्होंने इससे पहले की सरकार में जो पहला सामान्य बजट पेश किया था, उसका भाषण है। उसमें वे कहते हैं कि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के पांच उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विविधीकरण के माध्यम से कृषि विकास में तेजी लाना है। वह आगे कहते हैं:

अब मैं अपने एक बड़े स्वप्न की चर्चा करता हूं। जल किसी भी सभ्यता की जीवन रेखा है। हमें चेतावनी दी गयी है कि 21वीं शताब्दी में विश्व को जिस सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, वह जल का संकट होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि एक मिलियन से भी अधिक ऐसी संरचनाएं हैं, जिनमें से लगभग 5 लाख संरचनाओं का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। उनमें से बहुत–सी संरचनाओं का उपयोग ही नहीं किया जाता है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि कृषि से जुड़े सभी जल–निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनःस्थापना के लिए एक बड़ी योजना आरम्भ की जाए।

यह योजना आरंभ करने की घोषणा की गयी, पांच साल पूरे हो गए। मैं नहीं जानता कि इन पांच लाख में से कितने कुएं, कितने तालाबों, कितनी झीलों का पुनर्वास हुआ। अगर कृषि के लिए यही दृष्टिकोण रहेगा तो यह विकास दर चार प्रतिशत नहीं, मुझे शक है कि यह 1.6 प्रतिशत से भी कम होकर कहीं एक प्रतिशत न रह जाए। उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था।

फिर कहा गया कि दूध और दुग्ध उत्पादों में आनन्द मॉडल बहुत अधिक सफल रहा है। सरकार का एक बागवानी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। यह मामला भी कृषि से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं, इसका लक्ष्य बागवानी उत्पादन को 150 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से दोगुना करके वर्ष 2011–2012 तक 300 मिलियन टन करना है। हम इस समय वर्ष 2009–10 में हैं। मैं नहीं जानता हूं कि कृषि क्षेत्र में, बागवानी में या डेरी फार्मिंग में केन्द्रीय सरकार की किसी भी योजना से कोई प्रगति हुई हो और वह इतनी पर्याप्त हो कि हमारे कृषि उत्पादन को चार प्रतिशत तक पहुंचा सके। इसी तरह से कृषि कारोबार को बढ़ाने के लिए एक संगठन की स्थापना करने की बात कही गयी थी, उसका कहीं पर जिक्र नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक सिंचाई है,

पानी है, लेकिन उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। नदियां सूख रही हैं, ग्लेशियर्स सूख रहे हैं, जलस्तर भूमि के नीचे बहुत दूर तक जा चुका है, आप कैसे कृषि को उबारेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हवा से तो कृषि नहीं होगी। यहां बहुत से लोग हैं जो कृषि करते हैं, पानी जमीन के बाद मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं है। जमीन घट रही है, पानी घट रहा है, मगर कृषि में विकास दर को बढ़ाने की बात की जा रही है। यह विसंगति मेरी समझ में नहीं आ रही है।

कृषि के ऊपर जिस एक अन्य बात का घातक दुष्परिणाम होने वाला है वह जलवायु परिवर्तन है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर कभी माननीय वित्त मंत्री जी और उनकी सरकार जलवायु परिवर्तन के मामले में इस सदन में कोई गंभीर बहस, इस आशय से ही करे कि उसका असर इस देश की खेती पर, इस देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर, उद्योगों पर, इस देश के रोजगार पर क्या होगा। यह कहा जाता है कि बहुत दिनों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जा रहा है कि सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। मैं भी यह कहना चाहूंगा कि पेयजल हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और जीवन के अधिकार के साथ–साथ स्वच्छ पेयजल मिलने का अधिकार उसको दिया जाना चाहिए। यह एक लम्बी बात होगी, लेकिन अभी जो ग्लोबल ह्युमेनिटेरियन फोरम की रिपोर्ट है, जो 29 मई को श्री कोफी अन्नान जी द्वारा प्रकाशित हुई है, उसमें कहा गया है :

"Climate change is killing about 3,15,000 people a year through hunger, sickness and weather disaster, and the annual death toll is expected to rise to half-a-million by 2030"

अगर खेती में अनाज का उत्पादन कम होगा तो भूख बढ़ेगी। मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि दुनिया के 100 करोड़ भूखों में से 25 करोड़ से अधिक इस देश में निवास करते हैं। अगर कृषि नहीं बढ़ी तो यह भूख कैसे मिटेगी? आप इस देश को कैसे आगे ले जाएंगे? अगर जलवायु परिवर्तन के बारे में गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो फिर यह प्रश्न कैसे हल होगा? क्या हिन्दुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा भूखों, सबसे ज्यादा बेघरों का, सबसे ज्यादा कुपोषित लोगों का और सबसे ज्यादा बीमार लोगों का देश बनेगा? कृषि के माध्यम से ही आप लोगों को भोजन दे सकते हैं, बच्चों को भोजन दे सकते हैं, बच्चों की माताओं को भोजन दे सकते हैं। अगर देश में स्वस्थ माताएं और स्वस्थ बच्चे होंगे तभी इस देश के उत्पादन में, इस देश

की इकोनॉमिक एक्टीविटीज में आपको वृद्धि मिलेगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो आंकड़े हैं, उसमें स्टिंटेड ग्रोथ बढ रही है। मेंटली रिटार्डेड बच्चों की ग्रोथ बढती जा रही है, क्योंकि वे कुपोषित हैं। अगर बच्चा अंडरवेट है, उसे और उसकी मां को पोषण नहीं मिला है, तो वह बच्चा देश के लिए उपयोगी नागरिक नहीं हो सकता, वह देश पर भार होगा। वैसे भी इस देश में काफी मात्रा में भूख से पीड़ित, बेरोजगारी से ग्रसित और बीमारियों से परेशान जनसंख्या बढ रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, चाहे कृषि के बारे में हो या औषधियों की तरफ से हो या जल के कारण से हो, उस पर जितना बल आपके बजट में दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। उसका उल्लेख है, लेकिन उस बारे में गम्भीरता नहीं है। आपने कृषि विकास दर चार प्रतिशत रखने की बात कही है, तो इस तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हमारे देश में गरीबी बढती जा रही है। ग्लोबल इकॉनोमिक प्रोसेपेक्ट्स 2009 के लिए विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है, वह कहती है कि हम सिर्फ सब–सहारन कंट्रीज से आगे हैं, बाकी दुनिया में हम गरीबी के मामले में सबसे पीछे हैं। भारत में 12 मिलियन नए रोजगार पैदा करने का उद्देश्य दर्शाया गया है, जो गरीबी मिटाने के लिए आपके कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण चीज है। मैं जानना चाहता हूं कि गरीबी मिटाने के लिए आप क्या करेंगे? गरीबी की परिभाषा क्या है, पावर्टी लाइन किसे कहा जाएगा, क्या जो विश्व बैंक की परिभाषा है, वह मानी जाएगी या जो एनएसएस जो परिभाषित करता है, वह मानी जाएगी, जबकि उसकी भी दो–दो परिभाषाएं हैं या योजना आयोग जो कहे, उसे मानेंगे या कोई राज्य सरकार अपनी परिभाषा कर ले तो उसे मानेंगे या कैलोरी इनटेक को हम गरीबी की परिभाषा मानेंगे या आर्थिक वह कितना खर्च करता है उसे मानेंगे? सिर्फ खाने पर कितना खर्च करता है उसे मानेंगे, दवाई–कपड़े और मकान पर खर्चा भी शामिल होगा या नही, ये सब सवाल आपके बजट में कहीं आते हैं या नहीं? हमें यह बताया गया है कि हिन्दुस्तान में आपके आंकड़े आते हैं, उनसे लगता है कि कुछ गरीबी घटाई गई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पड़ौस के देशों में गरीबी तेजी से घटी है। उसे घटाने में बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे आगे हैं, चीन तो बहुत आगे है। ये आंकड़े कहते हैं कि 1990 में हमारे यहां 51.3 प्रतिशत एक्सट्रीम पावर्टी के लेवल पर थे,

जो 2005 में घटकर 41.6 प्रतिशत हो गए। लेकिन इसी दौरान चीन में यह स्थिति 60 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत तक हो गई। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर दो पड़ौसी देशों के बीच में, जिनकी समस्या लगभग समान है, जो लगभग एक ही समय आजाद हुए हों, वहां अगर प्रतिस्पर्धा में वह आगे बढ़ रहा हो और इस मामले में हम पिछड़ जाएं, तो वित्त मंत्री जी मुझे क्षमा करें, हम फौज का भी अच्छी तरह से निर्माण नहीं कर सकेंगे, शिक्षा का भी नहीं कर सकेंगे। इतनी बड़ी संख्या देश में गरीबों की रहेगी, तो यह चिंता का विषय हमारे लिए होगा। हम जानते हैं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे इस देश के अंदर आंतरिक सामाजिक असंतोष बढ़ेगा। देश में इससे डिवाइसिव टेंडेंसीज़ बढ़ेंगी। यह इन्क्लूसिव ग्रोथ के खिलाफ जा रहा है, यह डिवाइसिव ग्रोथ है। अगर 50 प्रतिशत लोग इसी तरह देश में पड़े रहेंगे तो बहुत मुश्किल बात होगी। अगर मैं अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के बारे में जिक्र करूं, तब तो स्थिति और भी भयावह है। रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अनुसार 77 प्रतिशत लोग 20 रुपए प्रतिदिन पर गुजर करते हैं। यह बहुत भयावह किस्म है। इस सारे असंगठित क्षेत्र के लिए इस बजट में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहेंगे कि ग्रामीण रोजगार योजना की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं और उससे हम नए रोजगार पैदा करेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसका जो परिणाम है, वह बहुत ही निराशाजनक है।

अभी आपके मंत्री महोदय ने बयान दिया है NRGEA is not working properly. वे कहते हैं कि 100 दिन का रोजगार कहीं भी नहीं दिया जा सका है, ज्यादातर राज्यों में 40 दिन, 42 दिन, 43 दिन से अधिक रोजगार नहीं मिला है। बहुत अधिक मात्रा में पैसे का क्षरण हुआ है और इनकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है। इनसे स्थाई रोजगार पैदा नहीं हो सकता है। यह अब एक तरह से अनएम्प्लाएमेंट बोझ है और उसमें काम नहीं हो रहा है। हम इस योजना में पैसा लगा रहे हैं, मुझे आपकी सद्–इच्छा पर मुझे कोई संदेह नहीं है आप जरूर चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए ही क्यों न हो, 100 दिनों के लिए ही क्यों न हो लोगों को काम मिलना चाहिए। वैसे तो आपने इसमें एक परिवर्तन कर दिया, जहां पहले घोषणा थी कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, अब शायद उसमें केवल प्रति–परिवार बीपीएल में एक ही व्यक्ति को रोजगार मिलता है। सवाल यह है कि यदि यह भी 42–43 दिन का ही है तो बाकी समय का क्या है? रिपोर्ट एक यह भी है कि बजाए इसके कि इससे वहां लोगों को रोजगार मिले, कुछ किसानों के सामने समस्या आ गयी

क्योंकि वे इस रेट के ऊपर देने में असमर्थ हैं। अच्छा हो अगर आप इस योजना के दूसरे पहलू पर भी विचार करें। क्या आप एम्प्लाएमेंट सब्सिडी एम्प्लायर को दे सकते हैं, जो एम्प्लाएमेंट जैनरेट करे। जो जितना ज्यादा एम्प्लाएमेंट जैनरेट करे, अगर उसे कुछ नुकसान या घाटा है तो उस दृष्टि से वहां भी घाटा पूरा किया जाएगा, ताकि उसे स्थाई रोजगार मिल सके। कोई संस्थान है, कोई इकोनॉमिक एक्टीविटी करने वाले लोग हैं, आप उनके लिए कोई नियम बना सकते हैं, कोई कसौटी बना सकते हैं लेकिन जब तक स्थाई रोजगार नहीं बनेगा, तब तक काम नहीं होगा। इस पहलू पर विचार करें, इस योजना का एक अंग यह भी हो सकता है कि एक परमानेंट रोजगार देने के लिए इस योजना के एक हिस्से का उपयोग किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर एग्रो–इंडस्ट्रीज का विस्तार किया जा सकता है और उनके एम्प्लायर्स को इस नीति से काम दिया जा सकता है। गांव में ऐसे बहुत से काम है जो भट्टे के, ईंट के, लकड़ी के, खेल–खिलौनों के, आचार–मुरब्बों के हैं। एग्रो–इंडस्ट्री से बहुत सा एम्प्लायमेंट जैनरेट हो सकता है। आप अगर इस तरफ भी सोचें, योजना का एक हिस्सा इस तरफ भी लाएं तो शायद कुछ लोगों को स्थाई रुप से रोजगार मिलेगा और उनको काम करने में सुविधा होगी। लेकिन यह चिंताजनक बात है कि जो परिणाम आ रहा है वह ज्यादा उत्साहपूर्ण नहीं है।

सारी दुनिया में गरीबी से लड़ने के लिए बड़े–बड़े देश ऊंची–ऊंची बातें करते हैं लेकिन उनकी नीयत हमें साफ नज़र नहीं आती है। मैं समझता हूं कि ऐसा हमारे देश में नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हम लोग सही मायने में गरीबी को दूर करना चाहते हैं। अगर इस मामले में कहीं पर भी हमारी जरूरत है, लोगों की गरीबी दूर करने के लिए, उनको दरिद्रता के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए तो हमारे नेता यहां बैठे हुए हैं और मैं बिल्कुल निःसंकोच कह सकता हूं कि हम इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। यह जानकर बहुत दुःख होता है जब कोई कहता है कि आप सिर्फ सब–सहारन कंट्रीज से ही आगे हैं, बाकी सबसे पीछे हैं।

सवाल यह आता है कि अनाज के दाम निरंतर बढते जा रहे हैं और हिंदुस्तान में अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि यह कैसी विडम्बना है कि सरकार कह रही है कि मुद्रा–विस्तार नैगेटिव हो गया, लेकिन खाद्यान्न और सब्जी के दाम निरंतर ऊंचे होते जा रहे हैं। अगर ये बढ़ा तो इंपऊलेशन के इंडैक्स के बारे में बड़ी फड़फड़ाहट है कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का

भयानक अंतर क्यों है? मुझे मालूम है कि आप भी इससे चिंतित हैं और प्रधान मंत्री जी भी इससे चिंतित हैं। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का पुनर्निर्धारण होना चाहिए और यह वस्तुस्थिति को सही बताए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि बजट में इस तरफ ध्यान देने की बात नहीं कही गयी है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का यह भेद और उनका रेशनलाइजेशन, उनको ठीक ढंग से निर्धारण करने की पद्धति विकसित की जानी चाहिए और यह जितनी जल्दी की जाए, उतना अच्छा है।

अगर खाद्यान्नों के दाम और बाकी दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढते गये तो फिर आप कितना भी पैसा इन योजनाओं में लगाएंगे, वह बेकार हो जाएगा, वह उत्पादक श्रम के लिए नहीं जाएगा, केवल आहार और दिनोंदिन चीजों की पूर्ति में लग जाएगा।

मेरा एक सुझाव है कि आप लक्ष्य निर्धारित करें कि हम हिंदुस्तान को भूख से मुक्त करें। भूख मुक्त हिंदुस्तान, कर्ज मुक्त किसान, यह है सम्पन्न भारत की पहचान। हिंदुस्तान में कोई भूखा न रहे। हिंदुस्तान में कोई किसान कर्जदार न रहे, प्राइवेट बैंक का भी नहीं और महाजन का भी नहीं। किसान को कर्ज लेने की जरूरत ही न पड़े। वह खेती में इनवेस्ट कर सके, उसकी इतनी आमदनी हो। जीरो हंगर – हम जीरो टालरेंस फार टेरेरिज्म करते हैं, जीरो टोलरेंस फार सो मैनी थिंग्स करते हैं, करप्शन के लिए करते हैं, क्या हम देश के सामने जीरो हंगर का लक्ष्य नहीं रख सकते हैं? तब आप चार प्रतिशत ग्रोथ बढ़ाने के लिए लोगों को उत्साहित करने के लिए प्रेरित करेंगे। यह बड़ा लक्ष्य है कि इस देश में कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए। 25 करोड़ लोग इस देश में रोज भूखे सोएं, यह किसी भी सरकार के लिए शोभनीय नहीं है। आपने कौटिल्य का उदाहरण दिया था, थोड़ा बहुत कौटिल्य मैंने भी पढ़ा है, उसने कहा है कि राजा का बहुत बड़ा दायित्व देश में अनाज पैदा करने का है। आपकी इजाजत हो, तो मैं चार लाइन पढ़ना चाहता हूं –

"Salutation to God Prajapati Kasyapa. Let the crops flourish always. Let the Goddess reside in the seeds and the grains."

अन्नं ब्रह्मः – इस रूप में अन्न पैदा हो, सारी फसल हमेशा लहलहाती रहे। शस्य श्यामला भूमि बनी रहे। वंदे मातरम, हम लोग यहां गाते हैं। उसी प्रकार की शस्य श्यामला भूमि वित्त मंत्री जी बनाइए। हम आपका साथ दें। आप यह लक्ष्य रखें, तो शायद देश को प्रेरित कर सकें। खाली बजट के आंकड़े

रखने से बात नहीं बनती है, balancing of the expenditure and revenue यह तो चार्टर्ड एकाउंटेंट भी कर लेता है, उसके लिए प्रणब मुखर्जी की जरूरत नहीं है। आज जरूरत इच्छाशक्ति और लक्ष्य की है। यदि आप हिन्दुस्तान को हंगर फ्री बनाएंगे, तो वह एक बड़ी बात होगी।

महोदय, मंत्री जी ने सोशल सिक्योरिटी और हेल्थकेयर का एक लक्ष्य रखा है। यह बहुत अच्छी बात है। देश का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, लेकिन वह कैसे होगा? हिन्दुस्तान में सोशल सिक्योरिटी की हालत यह है कि 0.25 प्रतिशत भी उसमें नहीं दे रहे हैं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में आपका प्लान का खर्च 18380 करोड़ रूपये है, जो कि पूरे प्लान आउट ले का 0.25 प्रतिशत भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप इस देश के लोगों को हेल्थकेयर कैसे दे सकते हैं? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में फैमिली प्लानिंग के नाम से जो चीजें चलती हैं, उस पर खर्चे हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसे बदलने की जरूरत है। मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी है, जिससे मुझे चिंता हुई है। इस देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देश में धीरे–धीरे बिगड़ रहा है। विश्व बैंक और डब्ल्यूएचओ के आंकड़े आपके पास हैं। मैं उसे कहना नहीं चाहता हूं और अच्छा भी नहीं लगता है। हमारे देश में इन्फेन्ट मोर्टेनेटी रेट इस समय क्या है? यह कहते हुए शर्म आती है कि प्रेगनेंट मदर्स की मृत्यु दर अभी घट नहीं पायी है। शर्म आती है, जब हम यह देखते हैं कि प्रीनेटल और पोस्ट–नेटल केयर नहीं है। हम देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में माताओं के लिए कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। मूल रूप से जहां से मानव संसाधन शुरू होता है, वहां यदि चिकित्सा ठीक नहीं है, तो चिंता होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैकसीन्स की कमी हो गई है। दिसम्बर 2008, "A team of Health Ministry officials toured 13 States to review the National Rural Health Mission. They found, among other things, hospitals in Bihar did not have vaccines for Diphtheria, Woofing Cough and Tetanus." यह वैकसीन्स बिहार सरकार नहीं बनाती है। यदि वह बनाती होती तो हम उन्हें दोष दे सकते थे। यह सरकारी कम्पनियों में बनते थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह बंद कर दी गईं और अब प्राइवेट कम्पनियों को वैकसीन्स बनाने का काम दे दिया गया है।

आज नतीजा यह है कि The review also reported shortages in Assam where measles vaccine was not available; in Chhattisgarh measles vaccine was in very short supply; in Kerala Diphtheria and Tetanus vaccines were in short supply in the primary healthcare

centres in Thiruvananthapuram and in Uttar Pradesh DPT and TT were not there. यह रिपोर्ट में लिखा है कि कितने बच्चे इसके अभाव में असमय में ही काल के गर्त में चले गये। गांवों में जहां अधिकतर पोलियो का तो बहुत जोर से प्रचार करते रहे हैं, कुछ काम होता भी रहा है, लेकिन टिटेनस हो जाए और एक स्थान पर जहां टिटेनस का इलाज होता है, उसे बच्चा मुर्दाघर कहा जाता है क्योंकि वहां कोई वैक्सीन नहीं है। डिप्थीरिया की वैक्सीन नहीं है, डीसीजी की वैक्सीन नहीं है, टी.बी. फैल जाए तो क्या होगा? एक तरफ हम मलेरिया और कालाजार की चिंता करते हैं लेकिन उसकी रिसर्च के बारे में हमारा कोई ध्यान नहीं है। मलेरिया और कालाजार इस देश को बहुत बड़ी मौत की तरफ धकेलने वाली बीमारियां हैं। ये फैमिली हैल्थ केअर का मतलब सिर्फ कंडोम्स का प्रचार करना नहीं होना चाहिए। उसका यह अर्थ होना चाहिए कि हमारे देश के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य मिले। वैक्सीन्स मिले, बच्चों को न्यूट्रिशंस मिले, प्रेगनेंट मदर्स को न्यूट्रिशंस मिले। उसकी तरफ ध्यान नहीं है और हैल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में यह बात स्वीकार की है:–

Vaccine shortage had affected India's vaccination programme in 2008. Shri Ramdoss said that compared to 2007 availability of DPT doses between April and December fell by 3.5 million in Bihar, 6.2 million in Uttar Pradesh and 3.3 million in West Bengal.

वह उपलब्ध नहीं है। जिन प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, उनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। मैं नहीं जानता कि वे कहां तक सच हैं और कहां तक गलत हैं? अगर वे सच हैं तो बहुत चिंता की बात है। देश में सरकार जो वैक्सीन दे रही थी, उनसे कई गुना दाम देने पर भी बाहर वैक्सीन नहीं मिल रहा है। जो एक बहुत चिंता की बात है। बजट में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह ठीक है कि आप एनआरईजी में पैसा लगा दें, आप किसी तरफ पैसा लगा दें, आप अपने मतदाताओं को धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करें

उन्होंने हमें वोट दिया है, हम आपको पैसा दे रहे हैं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि देश की सम्पूर्ण मूलभूत आर्थिक व्यवस्था का जो ढांचा है, जो बुनियाद है, उसको आप कमजोर करें।

अब मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूं कि अभी–अभी आज ही मेरे सामने रिपोर्ट आई है और बहुत चिंता की बात हो रही है कि इस बार सोइंग, बबाई बहुत कम हो गई है। आज के हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, इसे

आप देखें। उससे आपका यह 4 प्रतिशत तक जाने का सवाल कहीं होता ही नहीं है। बेरोजगारी दूर करने के लिए भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या करेंगे? आपने अपने बजट में एक्सपोर्ट के लिए कहा है कि आप एक्सपोर्ट में वृद्धि कराएंगे। Support Indian industry to meet the challenge of global competition and sustain the growth momentum in exports. बाहर की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? अभी एक रिपोर्ट मेरे सामने है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत चिंताजनक हालात पैदा करती है। यह बैंक ऑफ इंटरनेशनल सैटिलमेंट्स की रिपोर्ट है।

Mr. Joaquin Almunia Mira, Commissioner of Economic and Monetary Affairs of European Union said - Germany's economic output will shrink by six per cent; UK's economic output will shrink by four per cent; French economy will decline by three per cent; Italian economy will decline by 3.5 per cent; Romania's economy will decline by four per cent; Latvia's economy will shrink by 13.1 per cent; Slovakia's economy will decline by 2.6 per cent. Of the 27 nations in EU, only Cyprus will grow. European Union expects its recession to last till 2011 and 8.5 million Europeans will lose jobs over this period. With unemployment hitting 10.9 per cent in EU and 11.5 per cent in rural areas in 2010, EU has revived its GDP estimates for 2010 predicting a 0.1 per cent drop.

अगर वह सिकुड़ रही है तो इसमें हमारे एक्सपोर्ट की गुंजाइश नहीं है। आपको अपना एक्सपोर्ट सस्ता करना पड़ेगा, जब आप एक्सपोर्ट सस्ता करेंगे तो इसके लिए बहुत सोप्स इंडस्ट्री को देने पड़ेंगे और ड्यूटीज के बारे में विचार करना पड़ेगा। लेकिन आपके रिसोर्सिस क्या हैं? यह एक दुष्चक्र है, जिसमें हम फंस गए हैं। यह कहना कि वर्ष 2011 में यह सुधर जाएगा, मैं यह नहीं मानता हूं। आप मुझे पेसिमिस्ट कह सकते हैं, आप मुझे शंकाग्रस्त व्यक्ति कह सकते हैं। वित्त मंत्री जी, मैं पिछले बीस साल से निरंतर कह रहा हूं कि जो डेवलपमेंट मॉडल पश्चिम ने लिया है उसके ये परिणाम होने हैं, जो अवश्यंभावी थे और हो रहे हैं। आप उन परिणामों से बच नहीं सकते और ग्लोबल इकनॉमी को जोड़कर अपने यहां की समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते हैं। हम ग्लोब में हैं, दुनिया में हैं इसलिए अलग नहीं रह सकते। लकिन कितना जोड़ना है, कहां जोड़ना है और कैसे जोड़ना है, इस पर विचार करना होगा। इसके बारे में अब सारी दुनिया ही चिंता कर रही है कि क्या करें। अब बड़े पुराने इकनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के सलाहकार कह रहे हैं

कि ग्लोबलाइजेशन को सुधारने की जरूरत है।

It is not working in the interest of poor. It is not working in the interest of all. It does not represent inclusive growth. ये सब बातें स्टिकवाड्स कह रहा है, पॉल ग्रूपमैन कह रहा है, वांग हू कह रहा है, जो कोरियन इकनॉमिस्ट बहुत दिनों तक वर्ल्ड बैंक में रहे हैं। इस तरह से यह गड़बड़ हो रही है। हम उससे कितना जुड़ें, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। क्या हम सिर्फ उनकी इकनॉमी को ठीक करने के लिए अपनी इकनॉमी में बहुत से भूचाल लाते रहें? आज दुनिया के 40 देश अनाज पैदा नहीं कर रहे हैं लेकिन वे देश, जो अनाज पैदा कर रहे थे, उनके सामने संकट है। अमेरिका ने अपना सारा मेज़ इथनॉल बनाने में खर्च कर दिया और मेज़ के दाम बढ गए, गेहूं के दाम बढ गए। आप इस तरफ गौर कीजिए कि किस तरह जुड़ना है, कहां जुड़ना है और क्यों जुड़ना है। वित्त मंत्री जी आप भारत के वित्त मंत्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मंत्री हैं इसलिए आपका मुख्य काम भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना होना चाहिए। इसके लिए जितनी बाहरी सहायता की जरूरत होगी, जरूर लेंगे। बाहरी सहायता लेनी जरूरी है और इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दें, यह ठीक नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है। आप पश्चिम बंगाल से आते हैं और आपका साथ बसुदेव जी से रहा है, आप कुछ उनकी भी बात सुन सकते हैं और कुछ हमारी भी सुन सकते हैं। आप मिलकर कुछ कीजिए तभी शायद देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन अगर आप अमेरिका, यूरोपीय यूनियन या इन शक्तियों की तरफ देखेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा काम नहीं बनेगा। आप हिंदुस्तान की तरफ पहले देखिए और फिर जो जरूरत हो उसे देखिए। इसमें हम आपके साथ रहेंगे, इसमें हमारा आपसे कभी विरोध नहीं होगा। हमारा बराबर आग्रह है कि भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की बुद्धि, शक्ति और संसाधनों से सुधारने का प्रयास करें। इसमें जहां जरूरत होगी, वहां हम अवश्य मदद देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।

महोदय, आपने बजट में ग्रोथ की बात कही है। मैं देख रहा हूं कि इस बारे में लोगों का क्या कहना है। एक सवाल हिन्दुस्तान टाइम्स ने किया है, आप वह रिपोर्ट देख लें। अखबार कहता है – Has Budget 2009 put forward the right set of measures to achieve the projected nine per cent growth target? 'No', say 86 per cent. Has Budget 2009 fully met India incorporate's expectation from the Government? 'Yes' is the reply of 64 per cent. आपके बारे में यह धारणा है कि इंडिया इंक के

बारे में आपने काफी काम किया है लेकिन देश के वे लोग, जो ग्रोथ से जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि ग्रोथ होगी तो देश आगे बढ़ेगा, वे कहते हैं – नहीं। फिर कहा गया. Budget 2009 has struck with a GST roadmap deadline for 2010. Will it be met? 'No' say 75 per cent.

आपके जो लक्ष्य रखे जा रहे हैं, उनके बारे में अभी तक के जो रिएक्शंस हैं, वे नो में ज्यादा हैं, यस केवल उन लोगों के पक्ष में है, जो बड़े उद्योग चला रहे हैं। यह भी एक सोचने की बात है। अगर ऐसा है और लोगों में निराशा हो गई कि 9 परसैन्ट ग्रोथ की तरफ बजट नहीं बढ रहा है तो मैं समझता हूं कि आपको काफी कठिनाई होगी।

अब सवाल आता है कि आपने इस बजट में साधनों के बारे में क्या कहा। 6.8 परसैन्ट आपका फिस्कल डेफिसिट है। मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानता हूं कि विकास के लिए घाटा कोई गलत चीज नहीं है, उठाया जा सकता है, लेकिन वह प्रोडक्टिव इनवैस्टमैन्ट होना चाहिए। अगर वह नॉन–प्रोडक्टिव है, अगर वह सिर्फ लार्जेस बांटने के लिए है, अगर वह सिर्फ लोन ले–लेकर पैसा लुटाने के लिए है तो माफ कीजिए, वह देश में और अधिक मुद्रा विस्तार करेगा। मैं नहीं जानता कि आपका रोड मैप क्या है। आप कहां से पैसा लायेंगे और उसे किस तरह से इनवैस्ट करेंगे, यह एक बहस का सवाल है। बजट इस मामले में कुछ साफ नहीं करता। ये छः लाख करोड़ रुपये जो आप लायेंगे, ये कहां से लायेंगे? अब सवाल यह है कि आपने यह भी देखा होगा कि टैक्स जी.डी.पी. रेश्यो घट गया और घटता जा रहा है। अब तो घटता जा रहा है। अब आंकड़े घटने के है, 11 परसैन्ट पर आ गया है और अब जो वर्ष 2009–10 का बजट ऐस्टीमेट है, उसमें 10. 9 परसैन्ट है। यह बढनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ी। आप इस बार इसे बढ़ा नहीं सकते थे, मैं इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन यह भी तो बताइये कि आप ये साधन कहां से लायेंगे, विल यू मोनिटाइज। पिछले साल आपने करीब सवा लाख करोड़ रुपये की मुद्रा बाजार में फेंकी थी। क्या आप यह चार लाख करोड़ रुपये की मुद्रा बाजार में एक्स्ट्रा फिर से फेकेंगे? इसके क्या परिणाम होंगे? अमेरिकन्स आज परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो 700–800 बिलियन डॉलर्स बैंकों में झोंक दिये थे और अगर वहां इकोनोमी हीट अप हो गई तो आप देखिये, हमारा और आपका क्या बनेगा। इसलिए इस बात पर जरा गहराई से गौर कीजिए कि पैसा कहां से आयेगा? क्या विदेशों से लायेंगे, क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इनवैस्टमैन्ट होगा? वह किस

जगह करेंगे, वह गांव में तो नहीं करेंगे। वह आपके सोशल प्रायोरिटी सैक्टर्स में तो नहीं करेंगे। उनके इनवैस्टमैन्ट के क्या नतीजे होंगे। लॉंग टर्म के लिए इस पर सोचने की जरूरत है। हो सकता है कि इस वक्त आपको कुछ पैसे मिल जाएं और आप कहें कि देखिये यह करिश्मा हो गया या फिर आपने सोचा होगा कि यह आपका आखिरी बजट है, इसके बाद आप इसमें भाग नहीं लेंगे, तब तो अलग बात है, आप कर गये और आने वाला भुगते। इसकी बात मैं नहीं कहता। लेकिन अगर आप इस पर गौर करेंगे तो पता लगेगा कि यह बहुत गहराई से सोचने का समय है। क्या आप डिसइनवैस्ट करेंगे, कितना डिसइनवैस्ट करेंगे, क्यों डिसइनवैस्ट करेंगे, कैसे डिसइनवैस्ट करेंगे, फिर उस फंड का क्या होगा, जो डिसइनवैस्टमैन्ट फंड आपने बनाया है? जो कंपनियां इस समय लाभ से लबालब भरी हुई हैं, क्या आप उन्हें डिसइनवैस्ट करेंगे? वह ठीक है कि आप अपने जेवर बेचकर बनिये का उधार चुकाइये, वह कोई ऐसी बात नहीं है, गिरवी रख दीजिए। वहां मेरा ख्याल है आप कौटिल्य को भूल गये हैं और चार्वाक पर चले गये हैं – यावज्जीवेत सुखं जीवेत, त्रऽणं कृत्वा घृतं पिवेत। भस्मीभूतस्त देहस्य पुनरागमनं कुतो भवेत। वित्त मंत्री जी आप इस तरफ मत जाइये। देश के साधन जुटाइये। मैं देखता हूं कि आपने इंकम टैक्स में जो कमाल किया है, वह बहुत ही एक दर्शनीय चीज है। आपने सरचार्ज घटा दिया और हम लोगों को दस हजार रुपये की लॉलीपॉप दे दी। मैंने इसका आंकड़ा लगाया है, अगर किसी की एक लाख रुपये तक इनकम है तो उसे आज टैक्स नहीं देना पड़ता। दो लाख रुपये पर पहले हमें 5150 रुपये देना पड़ता था, अब यह 4120 रुपये हो गया है। 1030 रुपये की हमें पाकेट मनी मिल गई। इसके बाद तीन लाख, पांच लाख, सात लाख, दस लाख तक यही हालत है। मैं नहीं जानता यहां कितने लोगों की आमदनी दस लाख रुपये है। परंतु जिनकी दस लाख रुपये तक है, उन्हें 1030 रुपये का फायदा है। लेकिन जिनकी 15 लाख रुपये की आमदनी है, उन्हें 37,595 रुपये का फायदा है। जिनकी 50 लाख रुपये की आमदनी है, उनको एक लाख 45 हजार 745 रुपये की बचत है। यह इनकम टैक्स का खेल है, यह देखने की बात है। पहले तो हम खुश हुये कि हमारी आय की लिमिट 10 हजार रुपये बढ गई है। वित्त मंत्री जी समझते होंगे कि बड़े आदमियों के पास पैसा ज्यादा आयेगा तो वे बाजार में लायेंगे लेकिन जिन कामों में लायेंगे उससे आम आदमी का भला नहीं होगा। इससे देश का उत्पादन बढने वाला नहीं है। इससे देश में बेरोज़गारी मिटने वाली नहीं है।

वह रुपया एशो–आराम की चीजों में खर्च होगा। वह विदेशों में घूमने पर खर्च होगा। वह लग्ज़री गुड्स में खर्च होगा। वित्त मंत्री के बजट की दिशा मेरी समझ में नहीं आती है कि यह किधर जाना चाहता है? एक तरफ आप खेती की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं मगर बजट इससे अलग विपरीत दिशा में जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप गहराई से इस ओर ध्यान दें। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुये यह देखें कि इस साल जिस विभीषिका से देश गुजर रहा है, उससे ज्यादा विभीषिका में न फंसें. ।

उपाध्यक्ष जी, मुझे चिन्ता है कि जिस तरह का इस बार मौनसून है, क्लाइमेट चेंज है, इस साल अगर फसल 10–15–20 परसेंट भी कम हो गई तो आपको भारी कीमतों पर अनाज बाहर से आयात करना पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स हैं, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने चाणक्य को कोट करते हुये कहा था कि आने वाली विपत्ति को ध्यान में रखकर राजा को प्रबल सैन्य का प्रबंध कर लेना चाहिये। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप ऐसा प्रबंध करेंगे तो देश को विपत्ति से बचाने वाला होगा, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आपके बजट से देश पर विपत्ति आने की गुंजाइश होगी, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हम आपका समर्थन नहीं करेंगे।

धन्यवाद।

Synopsis

DR. MURLI MANOHAR JOSHI initiating the discussion, said: The hon. Finance Minister in his Budget speech has set some such targets which, if achieved, would make the whole country happy. It is easy to set the targets in the Budget speech but it is very difficult to mobilise the resources to achieve these targets. We are ready for any help required to streamline the economy of the country and improve the lot of the poor and the farmers. There is another grim picture before us. The pace at which the population of our country has increased, the foodgrain yield and the agriculture area has also decreased. Once the foodgrain production in the country was 202 kg per capita which has now come down to 191 kg. per capita. The

Government claims to increase the agricultural growth rate upto 4 percent. How it would be done? The allocation for agriculture and allied activities in this year's Budget is Rs. 10,629 crore which is just 1 percent of the total expenditure. The income of the farmers is decreasing. In such a situation it is very difficult to achieve the growth rate of 4 percent. Scarcity of water is a big problem for agriculture. What would the Government do in this regard? If this will be the attitude towards agriculture, then I doubt that this growth rate may be reduced to 1 percent. Less production of foodgrains will lead to hunger. I am sorry to say that out of the 100 crore hungry people of the world more than 25 crore live in our country. The population of hungry, unemployed and sick people is increasing in our country day-by-day. Therefore, I urge that attention should be paid towards it. I would like to know what steps the Government would take to eradicate poverty. As per the report of Arjun Sen Gupta 77 percent people live on Rs. 20 a day. This situation is quite alarming. What would the Government like to say for the unorganised sector in the country? 100 days employment could not be provided under NREGA. In most of the States 40-43 days employment was provided. It's monitoring is not proper. It would be better to give employment subsidy to the employer who may generate employment under this Scheme. The prices of foodgrains and vegetables are rising continuously. I am sorry to say that nothing has been said in this Budget in this regard. My suggestion is that the Government should set a target to make India hunger free. Can not we set the target of zero hunger? If we make India hunger free, it will be a big achievement. The hon. Minister has set some target with regard to social security and health care. It is a good thing. The condition of social security in our country is so grim that we are not allocating even 0.25 percent for it. The Plan Expenditure for health and family welfare is Rs. 18,380 crore, which is not even 0.25 percent of the total plan outlay. In such a situation how the Government would provide health care to the people of this country.

There is shortage of vaccines of Tetanus, Diphtheria and BCG in the country. Vaccine shortage has affected India's Vaccination Programme in 2008. We are not paying any attention towards research on Malaria and Kala-Azar. Family Health Care means people of the country get primary health facilities, vaccines. The

children and pregnant women should get nutrition. There is no mention of this in the Budget. The sowing has decreased during this crop season. It is a matter of grave concern. According to the experts, output of various economies of the world will shrink. If the output of these economies is shrinking then there is no scope

for increase in our export. In this situation, you have to reduce the prices of your export items and have to give a number of concessions to industries. I have been saying for the last 20 years that this would be the fate of development model of the West. Renowned economists and advisors of World Bank are saying that there is need of improving the globalisation. It is not working in the interest of the poor and the masses. It does not represent inclusive growth. We will need foreign assistance for improvement in our economy but this foreign assistance should not derail our economy. Fiscal deficit is 6.8 per cent. There is no harm in having fiscal deficit for development but it should be a productive investment. Tax GDP ratio is decreasing. It should be increased. Where from the Government will mobilize resources to achieve targets of the Budget? Will these resources be mobilized from other countries and will Government seek the route of Foreign Institutional Investment? They will not invest in social priority sectors. Therefore, we have to think of long term strategy. You are talking of agriculture, health and unemployment. But, the direction of the Budget is contrary to what you are saying. Keeping in view the trend of monsoon this season, if there is a decrease of 10 to 20 percent in production of foodgrains, the Government will have to import foodgrains at very high prices. The Government will have to pay attention to all these issues.

आम बजट में कृषि की उपेक्षा

&jk tukFk fl|g

गत 17 जुलाई 2009 को ''आम बजट 2009–10'' सत्र में कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद श्री राजनाथ सिंह ने कृषि, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण से जुड़े ज्वलंत प्रश्नों पर विस्तार अपने विचार रखे। हम यहां उनके भाषण के प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहे हैं।

- मैडम स्पीकर, जब से देश को स्वतंत्रता मिली हैं और ससंद में देश की प्रगति के विषय में गंभीर चिंतन–मनन प्रारम्भ हुआ है तब से देश के नीति निर्माताओं ने सर्वाधिक चिंता कृषि और किसानों की ही की है।
- 1950 के दशक में ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट कह दिया था।
- 'Eveything else can wait but not Agriculture'
- इस वाक्य को दोहराया है और हर बार संकल्प लिया कि इस बार कृषि का कायाकल्प किया जायेगा।लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात।
- पिछले पचास साठ सालों में जो कृषि की दुर्दशा हुई है इस पर मात्र पचास–साठ मिनट के भाषण या एक दो बहस के आयोजन से काम नहीं चलने वाला। यदि सरकार कृषि के प्रति वाकई गम्भीर है तो वह कृषि की समस्याओं पर विचार करने के लिए और समस्याओं के समाधान पर विमर्श करने के लिए पन्द्रह दिनों या कम से कम दस दिनों का संसद का विशेष सत्र अलग से बुलाये।

- मैं आज सरकार पर दोषारोपण करने की मंशा से यहां नहीं खड़ा हुआ हूं बल्कि उन ज्वलंत प्रश्नों की संसद में चर्चा करना चाहता हूं जिनका हल हर हाल में ढूंढना ही होगा।
- मैं मानता हूं कि भारत देश में यदि Agriculture पिस कर गई तो विकास का हर Model देर–सवेर फेल हो जायेगा।

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

- भारत के पास सम्भवतः विश्व का सबसे बड़ा Research and Extension System है जिसमें ICAR System के अन्तर्गत लगभग 100 शोध संस्थान काम कर रहे हैं। फिर भी क्या कारण है कि भारत में अधिकांश फसलों की उत्पादकता उन फसलों की Global Average Productivity से कम है?
- संसार की लगभग हर फसल इस देश के किसी न किसी हिस्से में उगायी जाती है। फिर भी क्या कारण है कि हम अपनी इस विविधता और क्षमता का पूरा लाभ नहीं ले पाते और कृषि उत्पादों के कुल वैश्विक व्यापार में भारत से होने वाले निर्यात दो फीसदी से भी कम हैं?
- अपने विशाल Consumer base के कारण आज भारत खाद्य पदार्थों और कृषि से संबंधित विश्व की अधिकांश बड़ी कंपनियों के लिए favourite destination माना जाता है। इसके बावजूद कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण का स्तर 2 फीसदी के नीचे है।
- Food processing के लिए सरकार जो नाम मात्र का बजट आबंटित करती है उससे हमारी इस क्षेत्र के प्रति गंभीरता साफ पता चलती है।
- साथ ही यह भी पता चलता है कि सरकार किसानों को उनके उत्पादों के Value addition का लाभ नहीं देना चाहती और न ही उन्हें बाजार से सीधा जोड़ना चाहती है।
- तमाम तकनीकी विकास और Advanced Research के बावजूद भारत में अभी तक एक चौथाई फल एवं सब्जियां Waste हो जाती हैं जो पूरे ब्रिटेन द्वारा उपभोग किए जाने वाले फलों एवं सब्जियों की मात्रा से कहीं अधिक है।
- सरकार की लगातार कोशिश के बावजूद क्यों अभी तक आधी से अधिक कृषि आबादी बैंकों की पहुंच से बाहर है।
- हालत तो इतनी गम्भीर है कि पिछले तीन सालों में किसानों के बेंक खातों की संख्या जो पहले करीब चार करोड़ थी। वह अब घटकर 3

करोड़ 60 लाख ही रह गई है।

- मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हर किसान का बैंक खाता अनिवार्य से क्यों नहीं खोला जा सकता?
- इस देश में सभी किसानों का बैंक में खाता आसानी से और अनिवार्य रूप से खोला जाना चाहिए।
- जहां व्यापार के वैश्वीकरण और उदारीकरण के चलते हमारी किसान WTO के आगमन के पश्चात वैश्विक प्रतिस्पर्धा से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और बड़े पैमाने पर Crop Shift Programme जैसे कामों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है।
- जहां इस देश में सिनेमा, खेल, खबर, फैशन अध्यात्म के लिए 300 से अधिक चैनल समर्पित हैं। कृषि के लिए एक भी चैनल नहीं है।
- NDA सरकार ने 2004 में किसानों के लिए एक टेलीविजन चैनल प्रारम्भ किया था मगर तीन महीने में ही UPA सरकार ने चैनल बंद कर दिया।
- मैं मांग करता हूं कि किसानों के लिए एक अलग से टीवी चैनल होना चाहिए जिससे कि कृषि की आधुनिक तकनीक की जानकारी आम किसानों तक पहुंचे।

कृषि की वर्तमान स्थिति

- कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान 1950 की 55 फीसदी की तुलना में घट कर महज 17 फीसदी रह गया है। जबकि खेती पर निर्भर आबादी में कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की गई है।
- कृषि क्षेत्र की औसत विकास दर पिछले साठ सालों में 2.5 फीसदी रही है।
- जहां कृषि का G.D.P. में योगदान लगभग 17 फीसदी का है। लेकिन कृषि एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए Plan Outlay महज 2 से 3 फीसदी तक ही सिमट गया है।
- पांचवी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने बुवाई किए गये कुल हेक्टेयर क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 63रूपये का खर्च किया गया। जबकि छठी योजना में 34 रूपये प्रति हेक्टेयर का खर्च किया गया जबकि सातवीं योजना में यह खर्च मात्र 18 रूपये ही रह गया है।
- सरकार द्वारा कृषि के प्रति उपेक्षा के रवैये के कारण ही देश में कृषि के मामले में वह परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जो भारत की Inherent

(इनहेरेंट) Strength के कारण होना चाहिए था।

- जब NDA की सरकार सत्ता में थी तो कृषि एवं अन्य सहयोगी क्षेत्रों में Gross Capital Formation की दर 11.7 फीसदी थी (2001–02)। NDA के शासन के दौरान अधिकांश समय कृषि में दस फीसदी GCF के आस–पास रही।

1999–2000	–	10.2%
2000–2001	–	9.7%
2001–2002	–	11.7%
2002–2003	–	10.3%
2003–2004	–	8.8%

- जबकि यूपीए सरकार के सत्ता में आते ही कृषि का GCF घट कर 7. 7 प्रतिशत हो गया।
- उसके बाद हर बजट में सरकार के वित्त मंत्री कृषि की चिंता में दुबले होते मगर कृषि का G.C.F. में योगदान बढ़ने के बजाय घटने लगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि का G.C.F. में योगदान अभी भी 7 फीसदी से अधिक नहीं है।
- पिछले कुछ सालों में लगभग सभी प्रमुख जींसों के उत्पादन में कमी आई है। दाल का 2008–09 में कुल उत्पादन 14.18 मिलियन टन का रहा जो 2007–08 की तुलना में 3.9 फीसदी कम है। इसी तरह नौ तिलहन फसलों का या 2008–09 में कुल उत्पादन 281.3 लाख टन ही रहा जो 2007–08 की तुलना में 5.5 फीसदी कम रहा।
- जबकि गन्ने के उत्पादन में तो 2008–09 में 16.9 प्रतिशत कमी दर्ज की गई है। 2007–08 में गन्ने का कुल उत्पादन 3482 लाख टन था जो 2008–09 में घटकर 2892 लाख टन ही रह गया।
- कपास का भी उत्पादन 10.1 फीसदी घटा है। 2007–08 में कपास का कुल उत्पादन 258.84 लाख गांठों का था जो 2008–09 में घटकर 232.68 लाख गांठ ही रहा गया है।
- हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश को दूसरे ग्रीन रिवोल्यूशन की आवश्यकता है। उन्होंने इस बारे में देश की जनता को आश्वासन भी दिया कि 2015 तक देश में खाद्यान्न उत्पादन 200–230 मिलियन टन से बढ़ा कर दुगुना कर दिया जायेगा।
- मगर सबसे अहम सवाल है कि हम इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे

- भारत को सिर्फ एक या दो ग्रीन रिवोल्यूशन की नहीं बल्कि एक एवरग्रीन रिवोल्यूशन की अधिक जरूरत है। इस इसके लिए उत्पादकता को सीधा बाजार और उपभोक्ताओं से जोड़ने की जरूरत है।
- खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की गति काफी शिथिल है। 2005–06 से 2007–08 तक यानि तीन सालों में कुल उत्पादन मात्र एक करोड़ टन बढ़ा है। जबकि लक्ष्य है 2015 तक कुल खाद्यान्न उत्पादन 40 करोड़ टन करने का।
- यदि सरकार तीन साल में 1 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन बढ़ायेगी तो 2015 तक हम मात्र 25 करोड़ तक ही पहुंच पायेंगे।
- 40 करोड़ टन तक पहुंचने में UPA सरकार को 45 साल लगेंगे।
- 2002–03 से 2007–08 तक देश की आवादी 8 फीसदी बढ़ी है। मगर खाद्यान्न उत्पादन में बमुश्किल 05 फीसदी की वृद्धि हुई है।
- सरकार को चाहिए था कि वह इस बजट में आवादी के मुकाबले खाद्यान्न उत्पादन में 3 प्रतिशत की शार्टफाल को पूरा करने की योजना बनाती।
- इस शॉर्ट फॉल को पूरा करने के लिए सरकार ने किसी भी योजना का कोई उल्लेख नहीं किया है।
- उम्मीद थी कि सरकार को दुबारा अवसर मिला है इसलिए कम से कम इस बार खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कोई रोडमैप इस बार बजट में प्रस्तुत किया जायेगा। मगर आश्चर्यजनक से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के संदर्भ में कोई चर्चा तक नहीं की गई है।
- यदि सरकार कृषि के विकास के प्रति वाकई गम्भीर होती तो कृषि के लिए बजट आवंटन में नाम मात्र की वृद्धि नहीं की गई होती। 2009–2010 के बजट में कृषि के लिए 10629 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई है जो पिछले बार की तुलना में मात्र 550 करोड़ अधिक है।
- कृषि के विकास के लिए बजट में कहा गया कि Credit Flow 2,87,000 करोड़ से बढ़ा कर 2009–10 में 3,25,000 करोड़ कर दिया जायेगा। मैं वित्तमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कृषि के लिए Credit availability बढ़ाई है। लेकिन यह राशि मंहगी व्याज दर पर दी जायेगी।
- लेकिन वित्त मंत्री जी ने बड़ी होश्यारी से जहां एक ओर कृषि के लिए

Credit Flow बढ़ाने की बात की तो दूसरी तरफ Intrest Subvention के लिए जारी धनराशि घटा दी।वित्त मंत्री ने बजट में कहा।

- To achieve this, I propose to continue the interest ubvention scheme for short-term crop loans to farmers for loans up to Rs three lakh per farmer at an interest rate of seven per cent per annum. I am also happy to announce that, for this year, the government shall pay an additional subvention (interest subsidy) of one percent as an incentive to those farmers who repay their short-term crop loans on schedule. Thus, the interest rates for these farmers will come down to six percent per annum. For this, I am making additional budget provisions of Rs 411 crore over interim budget estimate."
- जबकि Expenditure Budget के पेज 16 पर स्पष्ट लिखा है कि Short term credit का Interest subvention 2008–09 के 2600 करोड़ की अपेक्षा 2009–10 मे 2011 करोड़ कर दिया गया है।
- इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि बजट में यदि एक तरफ से राहत देने की बात की गई है तो दूसरी तरफ इसकी भी पक्की व्यवस्था की गई है कि इसका लाभ कम ही लोग उठा सके।
- देश में बांटे गये कर्ज की राशि पिछले तीन सालों में तिगुनी हो गई मगर कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या घट गई। कर्ज लेने वाले अधिकांश किसान बड़े किसान हैं जबकि छोटे और मझोले किसानों तक संस्थागत कर्ज की पहुंच नहीं है। 80 फीसदी छोटे और मझोले किसान गैर संस्थागत स्रोतो से कर्ज लेते हैं।
- 2008 में 71,000 करोड़ की कर्ज माफी की गई मगर इसका उपयोग किसानों को राहत देने से कहीं अधिक बैंकों की बैलेंसशीट को 'Bad Loans' से उबारने में अधिक हुआ।
- जिस तरह किसानों की Input Cost तेजी से बढ़ी है उसे ध्यान में रखते हुए किसानों को कृषि कार्यों के लिए दिए गये ऋण की ब्याजदर 4 फीसदी से अधिक नही होनी चाहिए।
- सूखे और बाढ़ की स्थिति में ब्याज की दर शून्य होनी चाहिए।
- ऐसा नहीं है कि सरकार इन बातों से परिचित नहीं है क्योंकि किसानों की आत्महत्याओं का जो दौर इस देश में चल रहा है, उसका मूलभूत कारण ऊंची ब्याज दरों पर कृषि ऋणों की उपलब्धता है।

- किसानों की ऋण माफी तात्कालिक उपाय है दीर्घकालीन नही। यदि कृषि का कल्याण करना है तो योजना और उपाय दोनों दीर्घकालीन ही होने चाहिए।

फसलों का बीमा

- कम ब्याजदर पर कृषि ऋण की चर्चा मैंने अभी की मगर उसके साथ Farm Income Insurance Scheme को लागू किया जाना भी उतना ही आवश्यक है ताकि किसानों की गारण्टीड Income सुनिश्चित की जा सके।
- वर्तमान समय में जो फसल बीमा योजना चल रही है उसका लाभ अभी तक देश के कम ही किसानों को मिल रहा है। मैं सरकार से इस संदर्भ में विस्तृत आंकड़े जानना चाहूंगा।
- साथ ही सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि मौसम और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के खतरे लगातार बढ़ने के बावजूद फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है।
- क्या वर्तमान फसल बीमा योजना को मोटर वाहन बीमा की तरह अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता? इस पर विचार होना चाहिए।
- जब मैं कृषि मंत्री था तो मैने एक अनोखी योजना बनाई थी, जिससे किसानों की आर्थिक सुरक्षा का चक्र मजबूत हो जाता। परन्तु इस योजना की प्रशंसा करने के बावजूद यू.पी.ए. सरकार ने इस ठण्डे बस्ते में डाल दिया।
- केन्द्र सरकार ने पिछले बजट में किसानों की ऋण माफी के लिए साठ हजार करोड़ रूपये आवंटित किये थे। मगर इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में उन किसानों को नहीं मिल सका था, जिन्होंने महाजनों से कर्ज लिया था।
- मुझे प्रसन्नता है कि इस बार बजट में इस तरफ भी ध्यान दिया गया है और मामले की विस्तृत जानकारी के लिए एक Task Force के गठन का प्रस्ताव रखा गया।
- लेकिन इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द अमल में लाते हुए Task Force को गठित करके Time Bound report प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
- शार्ट टर्म क्रेडिट के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड से काफी सहूलियत

हो सकती है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि ऐसी योजनाओं से लाभ लेने वाले किसानों की संख्या तेजी से नहीं बढ़ रही है।

- क्या कहीं Implementation के स्तर पर कमी है? या कोई अन्य Procedural समस्यायें हैं?
- इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए और कमियों को तत्काल दूर किया जाना चाहिए।

  इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखकर NDA सरकार ने राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया था जिसने 2006 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी मगर उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।
- यहां तक कि बजट में राष्ट्रीय कृषक आयोग की एक भी सिफारिश पर निर्णय लेना तो दूर इस पर preliminary step तक नहीं लिया गया है। इसी से समझ में आता है कि यह सरकार कृषि के लिए कितनी गम्भीर है।
- सरकार ने चुनाव से पहले और अब बजट में कुछ चुनिंदा sectors को stimulate करने के लिए तीन stimulus packages के साथ–साथ अन्य राहत प्रदान की है। परन्तु जब हम कृषि की बात करते हैं तो न तो चुनाव के पहले और न ही चुनाव के बाद प्रस्तुत बजट में कृषि के लिए कोई stimulus दिया।
- जबकि देश के सभी भागों में कृषि की productivity and profitability बढ़ाने के लिए एक Integrated Agricultural packages की आवश्यकता है।

Soil Health बनाये रखना आवश्यक

- जब NDA शासन में था तो उस समय इस समस्या की गम्भीरता को समझते हुये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के संबंध में कुछ दीर्घकालीन योजनायें बनायी गयी थीं जिसमें किसानों को Soil Health Card दिये जाने के साथ–साथ मृदा परीक्षण की प्रयोगशालाओं का आधुनिकिरण किये जाने पर विशेष बल दिया गया था।
- बिना Soil constitution समझे किसानों द्वारा उर्वरक का प्रयोग करने से मिट्टी की उत्पादकता घटनी निश्चित है।
- इस संबंध में इस बजट में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता थी। मगर आश्चर्य है कि बजट में इस बारे में भी चुप्पी है।
- मिट्टी में Nutrient Value बनी रहे इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की

आवश्यकता है। साथ ही जिन इलाकों की मिट्टी में पोषक तत्व की कमी है। वहां तो Soil Enrichment पर विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।

मानसून पर कृषि की निर्भरता

- भारत के किसान की मानसून पर अति निर्भरता उसकी स्थिति को मौसम के हाल की तरह बनाती है। इस साल भी कमजोर मानसून की खबर आ रही है। मगर सरकार की अभी भी इस स्थिति से निपटने की कोई खास तैयारी नही है।
- जबकि होना तो यह चाहिए था कि अब तक सरकार की तरफ से सूखे की स्थिति से निपटाने के के लिए एक एक्शन प्लान पर अमल प्रारम्भ हो जाना चाहिए था।

सिंचाई

- मिट्टी के साथ सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया जाना भी खाद्यान्न उत्पादन के लिए बेहद आवश्यक है। आज भी हमारे देश की कृषि सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है।
- इस साल मानसून ने थोड़ी आनाकानी क्या की कि पूरे कृषि मंत्रालय के हाथ पांव फूल गये है।
- मानसून पर भारतीय कृषि की अतिशय निर्भरता हमें संकट में डाल सकती है।
- जल का कुशल प्रबन्धन और उपयोग आज पानी की समस्या के युग में बहुत आवश्यक हो गया है।
- एक जल आन्दोलन शुरू किये जाने के साथ–साथ भूजल के दीर्घकालीन उपयोग के लिए नियम कानून बनाये जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- इस संदर्भ में राष्ट्रीय कृषक आयोग ने सरकार को detailed recommedation दी है परन्तु सरकार ने उन सभी को लेकर चुप्पी साध रखी है।
- सरकारी आंकडे गवाह हैं कि पिछली योजनाओं में हजारों करोड़ रूपये खर्च होने के बावजूद net irrigated area में बमुश्किल वृद्धि दर्ज की गई है।
- देश में मौजूद विशाल Rainfed Area जहां अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का कहर टूटता रहता है। इसके लिए सरकार ने एक National

Rainfed Area Authourity बनाई थी कि यह संस्था इन इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए कल्याणकारी योजनायें बनायेंगी मगर जब परीक्षा की घड़ी आयी है तो National Rainfed Area Authourity कुछ भी कर पाने में अपने को असमर्थ पा रही है।

उर्वरकों की कमी

- सिंचाई के साथ उर्वरक की उपलब्धता भी उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। सरकार आज तक पिछले पांच वर्षों से इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर पाई है।
- यह आश्चर्य का विषय है कि यूरिया का कुल उत्पादन 2002–03 में 187.27 लाख टन था। जो 2008–09 में मात्र 191 लाख टन तक ही पहुंच पाया है।
- जबकि DAP खाद का तो उत्पादन 2002–03 के 52.36 लाख टन की अपेक्षा घट कर 29.33 लाख टन ही रह गया है।
- यद्यपि सरकार यह दावा करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से किसानों को खाद की मंहगाई से बचाये रखा है।
- लेकिन सच्चाई यह है कि इस बार बजट में सरकार ने फर्टिलाईजर सब्सिडी के मद में पिछले साल की तुलना में 25 हजार करोड़ की कमी कर दी है।
- मैं यह मांग करता हूं कि फर्टिलाईजर सब्सिडी में की गई कटौती वापस ली जाए।

बीज

- उत्तम बीज कृषि के विकास का मूल आधार है। धीरे–धीरे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विकसित किये गये महंगे बीज इस देश के किसानों पर हावी हो रहे हैं।
- लेकिन सरकार अभी तक बीज अनुसंधान के लिए कोष बनाने के बारे में मौन है जिसके माध्यम से भारतीय कम्पनियां भी बीज का विकास कर सकें।
- न ही सरकार ने बीज की आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई न तो Seed Bank बनाया है और न ही कोई Seed Regulatory Authority बनाई है जो यह सुनिश्चित करे कि बीज के व्यापार में शामिल बड़े खिलाड़ी कोई घपला तो नहीं कर रहे या फिर किसानों के

साथ धोखा तो नहीं किया जा रहा है।

- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय बीज उद्योग विदेशी बीज कम्पनियों के मुकाबले कहीं कमजोर न पड़ने पाये।

किसानों को मिले उपज वाजिब दाम

- किसान को धरातल पर चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े वह अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिलने पर अपनी सारी पीड़ा भूल जाता है। दुर्भाग्यवश पिछले कई सालों से किसान को अपने पसीने की वाजिब कीमत भी नहीं मिल पा रही है।
- दावा किया जाता है कि किसानों को उनकी उपज वाजिब मूल्य मिले इसके लिए CACP की संस्तुतियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। परन्तु सच्चाई तो यह है कि न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय शायद ही कभी CACP की संस्तुति मानी जाती है।
- चाहे स्वामीनाथन कमेटी द्वारा किसानों को C2+50% फॉर्मूला हो या वाई. के. अलघ कमीशन द्वारा CACP को Statutory Status की बात हो MSP तय करने का स्थापित मापदण्ड नहीं है।
- जब मझोले किसानों को Crop diversification की एडवाइज दी जाये, तो उसे एम.एस.पी. का आश्वासन भी साथ में जोड़कर दिया जाना चाहिए।

अनाज भण्डारण की समस्या

- पिछले कुछ वर्षों से सरकार का Food management भी लड़खड़ा कर ध्वस्त हो गया है। एक समय था। NDA सरकार ने 640 लाख टन खाद्यान्न भण्डारण कर लिया था। और तभी काम के बदल अनाज जैसी जन कल्याणकारी योजनायें सफल साबित हुई। मगर यू.पी.ए. सरकार का Food grains का Managememt नाकाम साबित हुआ है।
- इस साल सूखे जैसी स्थिति बन रही है। क्योंकि मानसून ने अभी तक मेहरबानी नहीं की है। ऐसी परिस्थिति में हमें यदि यह पता चले की कि भण्डारण की खामियों के चलते हजारों टन अनाज उचित रख रखाव के अभाव में सड़ जाता है तो स्थिति और भी गम्भीर बन जाती है।
- राज्यों द्वारा खाद्यान्न की खरीद करवाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। FCI के पास जगह ही नहीं है।
- FCI ने भी यह स्वीकार किया है कि पिछले तीन सालों में करीब 1 लाख 10 हजार टन गेहूं चावल खराब हो गया है।

- आशा थी कि इस बजट में Storage Facility बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा क्योंकि सरकार National Food Security के लिए 3 रूपये प्रतिकिलो की दर से 25 किलो अनाज देने की योजना बना रही है।
- अनाज भण्डारण की कमी की समस्या से निपटने के लिए सरकार को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप में हर ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- चूँकि UPA सरकार Food Security बात करती है। इसलिए मैं उसे याद दिलाना चाहूंगा कि इस काम के लिए एक prompt delivery mechanism की आवश्यकता पड़ेगी।
- वर्तमान समय में जो PDS का delivery mechanism हैं वह काफी हद तक dysfunctional और भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। यदि गरीब और आम आदमी को सरकार वाकई राहत पहुंचाना हैं तो उसे तत्काल अपना PDS मजबूत करना पड़ेगा।
- भारत मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या हालात है इस संबंध में एन.सी. सक्सेना समिति कहती है कि कुल गरीबों में से मात्र 49.1 प्रतिशत लोगों के पास बी.पी.एल. या अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड है।
- सक्सेना समिति यह भी बताती है कि 23 फीसदी गरीबों के पास कोई राशन कार्ड नहीं है।
- सक्सेना समिति यह भी बताती है कि 17.4 फीसदी बी.पी.एल./अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड उन लोगों के पास भी हैं जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है।
- इसलिए National food security की दिशा में आगे बढ़ने से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

Land Use Policy में सुधार की आवश्यकता

- देश में किसानों की लैण्ड होल्डिंग्स छोटी है तथा बड़ी संख्या में लैण्डलेस Labourers मौजूद है।
- क्यों नहीं सरकार की तरफ से Work Land को Reclaim करने की कोई ऐसी पॉलिसी बनायी जाती है जिसमें भूमिहीन किसानों को भूमि वितरित की जाये ताकि उसका उपयोग कृषि के Allied Sectors को

मजबूत करने में किया जाये।
- Land Reforms का काम अभी अधूरा पड़ा है।
- कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग पर पाबंदी लगनी चाहिए।
- पानी को साझा संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए।
- Land Leasing Act और Contract farming Act ds provisions को Transparent Dynamic vkSj Farmer friendly बनाया जाना चाहिए।

कृषि के क्षेत्र में चुनौतियां और अवसर

- Marginal और favoured areas में Productivity gap कम होना चाहिए और अगले दस वर्षों में सिंचित भूमि की उत्पादकता 35 फीसदी और असिंचित भूमि की उत्पादकता औसतन 50 फीसदी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- पशुधन गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने, Farm Income बढ़ाने तथा ग्रामीण इलाकों में आजीविका बढ़ाने के बेहतर विकल्पों में से एक है। मगर वर्तमान बजट में सरकार ने इस बात की पूरी तरह उपेक्षा की है।

कृषि में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों

- भारत देश युवाओं का देश है और यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि बड़ी संख्या में देश के युवा बेरोजगार हैं। इसके बावजूद युवाओं को रूझान कृषि की तरफ नहीं है।
- कृषि में अधिक संख्या में युवा आयें और जो युवक इस काम में लगे हैं वे पलायन न करें इसके लिए कृषि को intellectually stimulating and economically rewarding बनाये जाने की आवश्यकता है।
- कृषि स्नातकों को हम क्यों नहीं Enterpreneur के रूप में विकसित करते हैं?

Extension Services में आई गिरावट

- तकनीक के क्षेत्र में मौजूद शिथिलता Extension Services में आई गिरावट को दूर करके तथा adequate quantity of quality inputs की supply सुनिश्चित करके देश में उत्पादकता को 150 से 200 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।
- आप सभी लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि उत्पादकता में आयी गिरावट को देखने के बावजूद भी Agriculture Research और Technology transfer के लिए Budgetary allocation में नाम मात्र की

भी वृद्धि नहीं की गई है।

कृषि का भविष्य

- आज पूरे विश्व की निगाह कृषि क्षेत्र पर है क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें Recession नहीं आता। Free market और Globalization के नाम पर Industry और Commerce के दरवाजे खोलने के बाद पश्चिमी देशों की निगाह भारत के विशाल Agriculture Sector पर लगी है।
- 2001 से WTO के माध्यम से कृषि सम्बन्धी मामलों में विकसित देश भारत जैसे विकासशील देशों की Arm twisting करने की कोशिश कर रहे हैं मगर अब तक उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है।
- जानकारी प्राप्त हुई है कि सितम्बर में भारत की राजधानी दिल्ली में ही प्रमुख देशों के वाणिज्य मंत्रियों को बुलाकर एक बैठक करके कुछ नरमी दिखाने की तैयारी की जा रही है।
- मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर एक भी कदम आगे बढ़ाने से पहले प्रतिपक्ष को भी विश्वास में लेना जरूरी है। इस देश का किसान ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें उसका उसकी कृषि से नियंत्रण ही खो जाये।
- भारत का किसान स्वावलम्बी बने इसके लिए सरकार को एक Integrated Action plan बनाना चाहिए।
- कृषि के वैश्वीकरण की सम्भावनायें भारत के WTO के सदस्य होने के कारण के कारण लगातार बलवती हो रही है और इस परिवर्तित माहौल में भारत किसान के अपने को काफी पिछड़ा महसूस करेगा। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपनी नीतियों को नई धार और नई दिशा देनी होगी।
- चूंकि फसलों की जैसी विविधता भारत में है। वैसी किसी देश के पास नहीं है इसलिए हमें Crop Planning के साथ –साथ किसानों को Incentive देकर उन फसलों की तरफ प्रेरित करना होगा जिनमें भारत की अच्छी संभावनायें हैं।
- दुनियां में कृषि का भविष्य उज्ज्वल देखा जा रहा है। और नये–नये प्रयोग आजमाये जा रहे है। अमरीका में स्थित अमरीकन सोसायटी ऑफ एग्रोनामी के अनुसार भविष्य में Agriculture और allied sector एक होकर Agroforestry के रूप में जाने जायेंगे। Agroforestry में पेड़,

पौधों के साथ तथा पशुधन का एक ऐसा balanced system तैयार होगा जो Biodirvesity के साथ–साथ Ecosystem को भी replenish (नई ऊर्जा से भर देगा) कर देगा।

- पश्चिमी देशों में तो Agriculture की तस्वीर बदलने की तैयारी जोरों पर है। परन्तु भारत में कृषि अभी भी उपेक्षित ही है। इस बार का बजट कृषि के मामले में पूरी तरह निराशाजनक साबित हुआ है। यह निराशा और भी दुखद है क्योकि सरकार ने अपने आर्थिक सर्वे में कृषि क्षेत्र की कई समस्याओं को स्वीकार किया है। परन्तु उनका समाधान ढूढ़ने की बजट में कोई गम्भीर कोशिश नहीं की गई।
- कृषि के बारे में सरकार को अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है। उसे कृषि को उद्योग के समकक्ष बल्कि उससे भी अधिक वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि कृषि में आया सुधार देश की दो तिहाई आबादी के जीवन को सीधा प्रभावित करता है।

Budget does not address any challenges before country

-M. Venkaiah Naidu

Mr. Deputy Chairman, Sir, I am happy to initiate the discussion on the Budget, 2009- 010. Sir, I must humbly say that I am not in agreement with many of the proposals made by the Finance Minister. Of course, I welcome certain initiatives. I will come to them later. Shri Pranab Babu, the Finance Minister is one of the most experienced politicians in the country. He has enough experience and ability also. But, I must also admit, Sir, that it is a great disappointment not only to me but also to the entire country because the country is facing challenges on each and every front and the national economy is facing a stiff challenge. The challenge is not only on account of global financial crisis but also on account of 'do nothing' policy of the Government. That is the biggest worry.

In the last five years, the UPA used to blame our Left friends saying that they are creating road blocks, they are acting like speed breakers and, then, we are not able to perform. Now, those speed breakers or road blocks are not there, the road is free. You have your own majority. Nothing stops you from taking hard decisions whenever necessary.

But, Sir, despite the assurance of political stability, the mindset of UPA is not development oriented. This is our conclusion. Of course, it has some positive aspects and as the BJP has declared in the beginning itself that we humbly accept the verdict of the people and, then, we have decided to function as a constructive Opposition. My Leader in the House here and my Leader in the other House

have made it very clear and they have said that, 'we are with the Government whenever Government needs our support in the larger interest of the country'. Sir, the major challenges that are there before the country are: firstly, the biggest challenge is price rise, the suffering of the common man; secondly, the loss of jobs, growing unemployment; thirdly, the agricultural crisis, the happenings in the rural India across the country are really disturbing, and, fourthly, and importantly is the economic slowdown, worldwide slowdown and slowdown in India. Also, Sir, the last is internal security.

What is happening in Kashmir, what is happening in Chhattisgarh, Orissa, Jharkhand, Maharashtra and in many parts of the country. It is the issue of Naxalism and the issue of insurgency in the North-East and the issue of separatist tendencies raking up their ugly head again in Jammu and Kashmir and the lack-lustre attitude of the Chief Minister. They are the challenges before the country, and, unfortunately, Sir, I must say that this Budget does not address any of these challenges. There is not even one line about price rise. I would have been happy if there is some discussion. There is no mention about it. Sir, he made a big statement even with regard to jobs. He said that 1.2 crore jobs would be created. What we are getting under NREGA is not job, it is a temporary wage. You are also not assured of job. Sir, Pranab Babu may have presented the first full-fledged Budget as the Finance Minister, but it is not a new Budget of the Government, because the Government is continuing. They have got a renewed mandate.

In the President's Speech and also on umpteen occasions they all said about it. I don't want to take time on that count. Sir, the present economic situation in the country is disturbing. If the off-Budget items and the States' deficit are added, the likely actual deficit will be over 13-14 per cent! It is mindboggling. This has never happened in the country. Earlier, the highest was 7.7 pre cent. And, Sir, you know the consequences of 1991 where we had to pledge our gold. Today, the Government has a total spending of Rs. 10.38 lakh crores. And, the Government is going to raise only 6.14 per cent by way of taxes and through other income. The borrowing itself is is Rs. 4 lakh plus crores! In real terms, it comes to almost 40 per cent of the total Budget expenditure which the Government is borrowing! This is the reality of the situation today.

Sir, after having made the country to suffer from the illusion of dream Budgets for the last five years, the exchequer has been landed into a catastrophic consequences. If you refer to the earlier speeches of the former Finance Minister you will know. I don't blame the present Finance Minister for those speeches. But, at the same time, the Government has a collective responsibility. It is the same Government, same party heading a coalition. If you go through them, you will know that.

Sir, the Economic Survey has detailed and outlined the road map for recovery. It has given certain concrete suggestions. It has identified the sectors where incentives need to be given. It has also identified sectors where the Government needs to invest. It has also given a clear-cut road map for the economic growth and the development of the country in the next five years. But, unfortunately, the honorable Finance Minister seems to have not cared for the finding or the opinions of the Economic Survey. Normally, Finance Ministers try to take advantage of the advice given by the Economic Survey, try to take certain cues from the findings and try to take certain hard decisions whenever necessary. But, unfortunately, this time it has not happened. Sir, the Economic Survey, of course, has a huge wish list. You have missed the bus on a number of occasions in the last five years. The big ticket reforms are missing. The Budget has nothing to offer in short-term. Neither any target fixed for fiscal prudence nor for food security or public sector disinvestment.

The hon. Finance Minister did not even mention about the far-reaching financial sector reforms suggested by the Survey, which include the Banking Regulation Bill, hiking of FDI in insurance sector,permitting 100 per cent in select insurance companies, Defence and in other sectors. That means, the Survey has not influenced or failed to influence the hon. Finance Minister and his officials to take corrective steps.

Sir, I say the Budget is unrealistic, not transparent and unlikely to stimulate the economy. High fiscal deficit, high interest rates, little exemptions, too little incentives and there is nothing more. If one has to describe it in 2-3 lines, this is how one can explain the Budget. Sir, it is a clear case of economic mismanagement by this and the previous Government. The fiscal management in the last five years has been miserable. Now, I come to what I said in the

beginning. Pranabbabu has become the Finance Minister and has presented a full-fledged Budget this time. The former Finance Minister was assuring the nation by saying that everything is fine and said we need not worry. Sir, I quote what Mr. Chidambaram said in Hindustan Times Conclave. He said, "India well insulated from the US financial crisis. There is no cause for alarm. I assure the Indian investors that domestic market fundamentals are quite strong and it is unlikely to face the negative effects of the financial sector collapse in the US. Despite some tightness, Indian economy would maintain a growth close to 8 per cent." I am quoting from what he had said in the Hindustan Times Conclave. Throughout the period, especially in the last one year, he had completely been denying, month after month, that the country was heading for a slowdown. Now, the Government is using 'international slowdown' as an excuse to cover up the consequences of its own mismanagement.

In the present economic slowdown, nobody expects wonders from the Finance Minister. I do understand the predicament that he is facing and the problems that he has inherited. It is very clear. But, at the same time, taking this as an opportunity, we thought that a senior person, at the helm of affairs of the Finance Ministry, will evolve a roadmap and will take the country forward. But that did not happen. He did not take bold measures. There cannot be inclusive growth without growth. We are all aware that growth is not possible without reforms. This has been our experience.

The previous Finance, Shri P. Chidamabaram, while presenting the Budget, last year, had said, "It is widely acknowledged that the fiscal position of the country has improved tremendously." Please underline, Sir, 'tremendously!'. He further said, "I am happy to report that the revenue deficit for the current year will be 1.4 per cent against the Budget estimates of 1.5 per cent, and the fiscal deficit will be 3.1 per cent against the Budget estimates of 3.3 per cent." This is what he had said one year back in the House. He is more capable in using very sophisticated words and Oxford English, which the people only like Farooqji and others can understand it. I am not a person of that calibre.I am a rural person, coming from a village background, having studied in a street side school.

He had used the words, "The fiscal position of the country has improved tremendously"!

And, he was happy to report that the fiscal deficit had come down and the revenue deficit had also come down. But what has happened, now, within this short period? He is, unfortunately, not there to explain. It has been left to the present Finance Minister. But, as I told you, the Government is a continuing institution. The same party is governing; the same Minister was there in the other Ministry. He also added, "Four years up to 2007-08 have been the best years so far. But, I may say with humility, the best is yet to come". This is what he had said. And, now, he has left that best to Shri Pranab Mukherjee to tackle. Who has to be held responsible for this economic gloom? I don't hold the present Finance Minister responsible individually. But, at the same time, as I told you, I am pressing once again, it is the collective responsibility of the Government. And, the Congress has continuously been in power. Even the Prime Minister and the Finance Minister had been assuring all of us that India would not be affected by the slowdown, as our fundamentals were strong. But nobody is able to explain what has happened suddenly. He said, "My Government, the Indian Government has really taken initiative." And, those efforts started bearing fruits after you came to power! Sir, let me recall the economic scenario, the great initiatives taken by our great leader, Shri Atal Bihar Vajpayee -- the air connectivity, the rail connectivity, the highway connectivity, the rural connectivity, the T.V. connectivity, the port connectivity, the strengthening of the rupee, the highest foreign exchange reserves, the lowest inflation, no line, no queue, no waiting list, no shortage, no black-market, no rationing of LPG cylinders, as proposed, now. That was the situation. And, you had inherited that. Let me quote from the National Sample Survey,

".....reveals faster increase in employment during 1999-2005, as compared to 1983-1994." The source is the Economic Survey, 2006-07. 'Faster increase in the employment' during that particular period. So, the employment was high, the rupee was strong, the foreign exchange reserves were comfortable, foodgrain situation was also comfortable. I would also like to quote my friend, Shri Chidambaramji, while submitting the Economic Survey in Parliament in 2004, he had, in the very opening sentence, said, "

The economy appears to be in a resilient mode in terms of growth, inflation, balance of payments -- a combination that offers

large scope for consolidation of growth momentum and micro-economic stability." This was the first sentence of the Economic Survey, which was presented by your Government after we demitted office and you came to power. So, you cannot blame the earlier Government saying that it was all in a mess, and, then we tried our best in the five years and we have failed. We had given you a robust economy. You have also said, Sir, "The economy enjoyed the benefits of relatively low inflation with comfortable stocks of foodgrains, enhanced competition product markets and an appropriate mix of fiscal and monetary policies." And, Sir, about the food management, it says, "Double digit annual average inflation - rate of 10 per cent, between 1991-92 and 1995-96." When our hon. Prime Minister was the Finance Minister, it came down to 4.2 per cent. Sir, the hon. Prime Minister's name is not there in the quote. Don't misunderstand me; I am recollecting just for the sake of refreshing the memory. During 2003-04, the last three years of NDA rule, it came down to 4.2 per cent. This was admitted in the Economic Survey by the Finance Minister. He said, "comfortable supply situation, remarkable price stability, investment of foodgrains in different parts of the country -- despite 2002 poor monsoon, there was a drought in 14 States at that time, we demonstrated the relevance of food security system-- and lastly, Sir, while presenting the Budget on 8th July, the Finance Minister admitted that the achievements of the NDA Government were, the economic fundamentals appeared strong and the balance of payments was robust. That was the situation. This was what you had inherited. And, what is it that you have done in the last five years? Now, the Finance Minister says proudly, of course, we are proud, that we are going to spend more than Rupees ten lakh crores.

As an Indian, as an ordinary person, forgetting the political affiliations, we are all happy that India is able to have a Budget of Rs.10,00,000 crores plus and that is being presented by our hon. Finance Minister. But, at the same time, Sir, out of this, we are going to spend Rs.6,18,834 crores for the non-Plan Revenue Expenditure, which is totally unproductive -- Interest payment, pension subsidies, establishment charges, etc. and, Sir, the Plan Expenditure is only Rs.3,25,149 crores -- not even half of the total non- Plan expenditure. How can anybody rationalize this, or explain

this? Then, the debt service burden is Rs.5,68,400 crores; interest payments alone is Rs.2,25,500 crores. Sir, it is mind boggling, if you have to pay that much of interest. If you borrow Rs.10è- you have to pay Rs.3è- as interest and out of every Rs.10è- you want to spend, you have to borrow Rs.4è- from the market. This is not an acceptable situation.

As I said in the beginning itself before Pranabbabu came, I am not an expert, I come from a humble village background, I have little common sense in politics, with some knowledge in agriculture, because that is the basic culture of our country, but, unfortunately, these figures, Sir, are really disturbing. I must admit today in the House, Sir, normally, I speak extempore on any subject in the House except on the WTO, NPT, CTBT, GDP, etc. I tried my best to understand some of it in the last few days. I have gone through the articles written by important people, the economists; I have gone through each and every editorial of the newspaper also; I must also admit I have consulted with some of my other well-wisher friends also, but I am not able to understand it personally. Sir, after I said, it is the beginning of the year; the Government has just started functioning; I don't find fault with them for each and everything, but, at the same time, what is the direction? How are you going to meet the expectations? That is the issue and on that there is a great disappointment in this Budget. Sir, this year, it will borrow Rs.4,00,996 crores -- around Rs.1,100 crores for every day. Rs.1,100 crores every day of this year! How can anybody expect us to service the debt? What are the resources? There are great eminent people sitting here, Bimal Jalanji is here and Rangarajanji is also here, I will be very happy if they are alert in the House and indicate some of us and give re-assurance to the people of the country that there is nothing to worry, nothing to worry. Okay. Even then, we would try to understand it also. But for an ordinary person, as I told you, coming from a village background, I am not able to understand how this is going to happen. Sir, if the Government is going to borrow more than Rs.4,00,000 crores, then, there will be pressure on the banks, there will be pressure on the public money. Then, what will happen to the private borrowers? I saw the other day, the hon. Finance Minister held a meeting and assured people saying 'nothing to worry, private people will also get money.' From where? The

interest rates will go up.

In an economic jargon, my friend, Arun Jaitley, was telling me, just now, that there is a phrase called as 'hedging out.' The people normally would look to the Government. The banks would also normally like to place their funds in bonds of the Government, rather than putting it in the private sector, which is facing difficulties. Then, how do you expect the private sector to function and then bring the socalled stimulus in the market and also take care of the employment generation or infrastructure creation? Sir, out of the extra expenditure of Rs. 1,20,000 crore, proposed in 2009-10 Budget over the previous year, Rs. 44,000 crore are going to go on account of Sixth Pay Commission.

If I am wrong anywhere, I will be very happy to be corrected by the Finance Minister. Then, Rs. 33,000 crore will go for extra infrastructure, Rs. 10,000 crore will go for non-Plan grants to States; and, Rs. 10,000 crore for contribution to the IMF's loan to PSUs. These add up to Rs. 97,000 crore. Sir, because of the fall in the fertilizer subsidy and allied items by Rs. 29,000 crore, this gross extra expenditure gets reduced to Rs. 78,000 crore. But not a single rupee out of this is stimulus to counter the slowdown. It is only the Plan allocation of Rs. 42,000 crore that includes the extra provision he had made for the NREGA. That will pass the test of stimulus. The other things are all marginal, according to me.

Sir, the bulk of the massive expenditure increased due to the interest payments, defence, subsidies, salaries and pensions. Even the economic expert, former Adviser, Shri Shankar Acharya, opines the same. The people expect the Finance Minister to take the nation into confidence, utilise this opportunity, avail the caution and advice given by the Economic Survey and then frankly place before the nation the roadmap he intends to do, which he is not doing. It is a great disappointment. Shri Pranab Babu is known for his frank views. He does not care and I read somewhere that he said, 'it is his last election.' That is not an important issue for us. Even otherwise, normally, he doesn't care; he is very frank. But on the Budget, he did not take the country into confidence and frankly explained what are the pros and cons.

Sir, he said that 'extraordinary situation requires extraordinary steps.' Sir, I would like to know where are those extraordinary steps.

What are the extraordinary steps? Except that you are going to spend extraordinarily and you are going to borrow extraordinarily, I don't find anything extraordinary in the Budget. That is why I said in the beginning itself, before Pranab Babu came to the House, that though I admire him, he has disappointed me and he has disappointed the nation.

Sir, some experts are warning that the country is moving towards a stagflation. I wish it doesn't happen. I don't want to frighten the people and I am not an expert also. But, at the same time, there are indications that the situation is going to be deteriorating. Sir, he has not outlined how the Budget is going to take care of the deficits. The States also require Rs. 1,50,000 crores. That means, the total market borrowing in 2009-10 is four times higher than the amount envisaged in 2008-09 Budget, taking even the States' borrowing requirements also. Sir, together, taking the fiscal deficit of the States and Centre, it is going to reach 12 per cent of the GDP. In the first two months, the Centre and States borrowed Rs. 1,89,691 crores, that is, 82 per cent more than compared to the same period of the last year. The Budget, Sir, with the additional expenditure by Government will draw funds from the market, and, subsequently, it will squeeze funds for the private sector. I have already talked about it. Sir, the Chairman of the State Bank of India, after he met the RBI Chairman, came out and told the Press, 'when the credit growth picks up and all the Government borrowings take place, it could stabilise there or harden.' So, an indication has been given by the principal banker. Sir, then our Finance Minister wants to ride out the slowdown through more spending and more borrowing as raising interest rates can hamper growth. This is not an answer at all. Sir, now how the RBI is going to act, that also has to be seen. How is it going to facilitate the private sector?

If the RBI doesn't act in a manner it is expected to and goes by the FM's risk, the robust growth will not pay off. Sir, there is no mention about the Raghuram Rajan Committee Report on Economic Reform. There is no mention about sectoral targets. The conventional course adopted by the Finance Minister has been to give push to reforms, so that economic activity can be generated. That has been the practice so far. Conscious of the fact that the trickle down effect is slow, reforms have two major advantages.

Some trickle down would take place in terms of generating employment and reducing poverty, and enhanced revenues in the hands of the Government could be used for social sector and poverty alleviation programmes. But in this Budget, the Finance Minister has decided to abandon reforms completely. I do not know if that is the view of this Government. He came out with the Budget of the 1960s. Sir, that spending at the bottom would have a trickle up effect and automatically improve the situation is his wisdom. If he proves to be right, we would be more than happy. You may win a political point, but we would be more than happy in the larger interests of the country. Then, Sir, it is said that trickle up effects would be faced with inadequacy of investments being made and the possibility of huge leakage would further dampen its desired effect. It is not that easy. Even if he intends to spend Rs. 100 and tries to send it through the direct pipeline, how much of it goes to the common man is everybody's knowledge. I do not blame this Government or that Government or even the Government in the States, but that is the reality of the situation.

Sir, the Finance Ministers earlier and the UPA have always been talking of economic reforms. I would like to know one thing here. You have been in power for so many years since Independence. The Congress has ruled the country for the longest number of years. That they have ruled and ruined is a different matter! But, at the same time, you have no excuses. We had been in power only for five to six years. I have already mentioned what we have done in those five to six years. But, was that long period not sufficient to reduce poverty considerably? Was it not sufficient to tackle the problem of unemployment? Was it not sufficient to tackle the regional imbalances? Was it not sufficient to have a level-playing field for the private sector vis-a-vis the Government sector? Do you need more time?

As we see, Air India is now asking for a big package. There is no problem in giving them big packages. My friends from Hyderabad, including my friend who is President of the Congress Party in Andhra Pradesh, were travelling from Hyderabad to Delhi. It took them four hours and two or three times they felt they were gone! But, fortunately, they came back. वह भी मैकेनिकल प्राब्लम थी। कल भी मुम्बई–कोलकाता फ्लाइट take-off करने के बाद थोड़ी–बहुत चक्कर मार

कर वापस आ गई, वह भी mechanical problem थी। उसके पहले भी एक दिन ऐसा ही हुआ, वह भी एक mechanical problem थी। Mechanical problem केवल वहीं हो रही है। मैं किसी एक संस्था की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। It was given sufficient time and we had expected that Air India would improve its functioning, increase its efficiency and even compete with others. Enough time has been given already. We should give time to the public sector also. Public sector is also equally important in this country. We are not against the public sector. But there has to be a healthy competition. How long will it take? I am of the considered view, whether you agree or not, that the Government has no business to be in business. Government making chicken biryani, running hotels, producing cycles and motorcyles and telling people they incurred loss because we did not prepare proper biryani; please, pay some tax -- all this is not acceptable. Those days have gone; those days of Government running hotels and other private businesses have gone. Steel factories and big infrastructure projects were set up. Late Shri Jawaharlal Nehru had the wisdom at that time to set up industries. At that time there was no IDBI; there were no international financial agencies; there were not enough private money in the country. He had set up different industries in different parts of the country; it was a wise move. That is a good thing; we are not opposed to that. But today, with the private sector coming in in a major way and with many international agencies to fund your projects, is there any need for the Government to go and try to burn its hands? This is another important thing, Sir. सर, बिजली, सड़क, पानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य स्व–रोजगार, इन सब विषयों के बारे में इतने साल में हम क्या कर पाए, क्यों नहीं कर पाए,टारगेट क्यों नहीं पूरा कर पाए? इसका समाधान हमसे ज्यादा आप लोगों को देना पड़ेगा। इसका कारण है कि हम सत्ता में केवल 6 साल रहे।

You cannot say in six years, the bijli has gone, water has gone and roads have become narrow. World class roads were built by our Government and they were a great addition;

India's image has gone up because of the connectivity revolution brought in by Shri Atal Behari Vajpayee. Sir, we have reports; I would seek the guidance of Shri Pranab Mukherjee and his team of officers here. According to the N.C. Saxena Committee report, 50

per of India's people live in poverty. How this figure has come? Shri Arjun Sengupta Panel says that the poverty is 80 per cent. Eighty per cent poverty in India after 62 years of Independence, after so many Five Year Plans! What is happening to our system? I am not trying to criticise him. I am trying to enlighten myself. I would like to be enlightened by the hon. Finance Minister about these figures. How can there be that much variation? Our Planning Commission says that 27 per cent people of the country are living below the poverty line. That is the situation. Sir, fifty-plus years you have been in power.

So, you have no excuse. For the last five years you have been in power. You have no excuses. Sir, the Finance Minister gave a small para No.55 about the organised and informal sector of our economy which, Pranab Babu himself concedes, accounts 92 per cent of employment and absorbs the bulk of the annual increase in our labour force. It is a good statement. But where is the provision? What are the steps to take care of 92 per cent -- weavers, fishermen, goldsmiths, blacksmiths and so on. People and goldsmiths are saying what is this branded jewellery. We don't prepare it; we don't manufacture it. Duty exemption is given to branded jewellery. I have no grouse against Tata or Ambani or Singhania or anybody. They are also part of our country. I am very clear on that. They are also adding to our wealth. If they follow the rules, fine. If they don't follow the rules, action has to be taken against anybody whoever it is. But the issue of the matter is that you give priority to branded jewellery.

Pranab Babu was telling that women would not be happy with my other measures, but they will be happy by this branded jewellery. I asked my wife. She said, what is branded jewellery? I have to explain her. She said, "We go to the goldsmith in our village and try to make ornaments of our likings and choice. That provides them employment and that also provides satisfaction to women. Then it really helps us." I don't think that this exemption to branded jewellery is going to help the common man and these 92 per cent people. Sir, you left them with one para. I am not saying that have ten paras and don't do anything, and that is going to help anybody. But my point is that it speaks of the intention of the Government and priority of the Government. Per capita income of the common man in the

last five years has fallen from 7.3 per cent to 4.5 per cent. Sir, what the foreign media experts are saying? I am not saying that you must go by their comments or statement. But you are expecting investment and you are in a different regime now where you have liberalisation, privatisation and globalisation. You are living in such type of regime whether you like it or not. So, one has to take care of the public opinion of the world also.

The World Bank says 4 per cent growth looking optimistic... Prem Shankar Jha. Sri Shankar Acharya says, it is timid on economic reforms and imprudent on fiscal management. The Wall Street Journal heading, "A Budget for second-tier developing nation." Comments about the budget, "That was, in sum, a pretty dreadful spectacle." BBC comments, "The market is worried about the new Government. What it will do to fund its increasing deficit."

"India's BBB-minus sovereign rating, placed on the negative outlook in February .." by Standard and Poor's analyst Takahar Ogawa. All these things are going to affect our growth and our economy. The country needs big dose of investment from business and also from the Government, and the Government's hands are very tight. For business people, there are no incentives to invest in the present atmosphere and the present scenario. It is not that Shri Atal Behari Vajpayee or the BJP or the Finance Minister at that time brought money from their pocket and built these roads. When roads project was initiated, I remember very well, there was some opposition. People said, what is this? How do you borrow that to Ambani and then this BOT and then this toll gate? How many times one has to stop between Chennai to Kolkata? Then answer was, how many hours are you travelling from Chennai to Kolkata? How much advantage you are going to get with regard to fuels, with regard to time, etc. Sir, today the result is before us. We have world-class roads and people are happy. They don't bother to pay toll for a particular purpose.

Sir, even the Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana was a very good programme initiated by the Government. I am happy that you said, you are continuing, and, I hope that you will put in more money for the Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana though there is no toll-gate; because there is no gate, that is why, you cannot have toll also in the villages. Ordinary roads are there. People are

saying, you are thinking of highways; there are highways here but no-way in the villages. You have a bye-pass to the towns, no pass in the village. We have to give more priority to the rural roads. I am happy that the Finance Minister said about it. I hope that you will translate it into action.

Sir, coming to countering the effects of the global economic shocks, we expected a judicious combination of tax-cuts and increase in spending to tackle the situation. On the last day of polling, your Government, your Ministers were telling us that the growth rate would be at 8.7 per cent. I have the press-cuttings with me; if you want, I can show also. Now, they are admitting that it is 6.8 per cent. Within one or two months, how could this happen. You tried to make people believe that everything was fine. Now, suddenly, you are saying, things have changed because of the international situation. It has been fashion for the Congress Party that whenever they are in trouble, they would accuse foreign hand, forgetting their own hands and forgetting what did they do in this country. Sir, coming to the direct tax exemption, we, the BJP wanted the exemption limit to be raised to Rs. 3 lakhs, and, Rs. 3.5 lakhs in case of women and ex-armymen. Finance Minister has given a meagre amount of Rs. 10,000è-, Rs. 15,000è- It is peanuts, Sir. In the present situation, where you have the Sixth Pay Commission's recommendations accepted, ordinary employee has to save. How much money is he saving? Sir, as per one figure, it is going to be Rs. 129è- per month for people who are getting exemption of Rs. 15,000è-. For people who are getting Rs. 10,000è- exemption, this amount is Rs. 86è- per month. Sir, eighty-six rupees per month exemption, is it a big hike in the present day situation? What do you get for Rs. 86è- today in the present market; not even three kilograms of sugar. Sir, this is another great disappointment. We expected him to be generous to the common people. You have removed the surcharge. It is fine. We welcome it. But only people who are having income above Rs. 10 lakhs, are happy, and, people, who are having income above Rs. 2 lakhs, are unhappy. Where is your focus? Where is your thrust? Are you concerned about the common man, middle-class, salaried people or are you concerned about other people. I have no quarrel. I welcome the step; even removal of surcharge is a bold step. I must admit it. But people will be watching it. They may not

understand. Kalavatis may not understand this economics; that is your fortune. But, at the same time, a reasonable number of people understand what has been happening, and, which direction the Government is going.

You have removed the Fringe Benefit Tax. Now, there is a doubt. The Fringe Benefit Tax is now abolished for the employer and passed on to the mployee. The employee has to pay the tax in future. I would be happy if the Finance Minister clarifies this point during his reply. On the one hand, you have given benefit to the employer, and, on the other, the employer has been burdened by raising the Minimum Alternative Tax, MAT, from ten to fifteen per cent. Sir, people expected the service tax on renting immovable properties to be abolished, and, people also thought that you would give some incentives to tourism, tax holidays for hotels and other things, which will improve the tourism aspect in the country. There is another disappointment, Sir, about one-rank, one pension. I also seek the guidance and enlightenment from the Finance Minister because of the divergent versions. Some of the people came and met us also. The Finance Minister announced that long-standing demand of the armed forces with regard to one rank-one pension has been accepted. Sir, it appears that two minor dichotomies between the pre-1996 and post- 1996 retirees have been rectified pursuant to the order of the Supreme Court. Am I correct? The Finance Minister can enlighten us. The most important demand was that those retiring after 1.1.2006 should be given parity with those retiring before 1.1.2006. This demand seems to have not been accepted by the Finance Minister. This is the apprehension amongst the Armed Forces' retired people. I am very happy if while responding, the Government comes out with a clarification.

Sir, there is another disappointment also. When Shri L.K. Advani ji wrote a letter to the Prime Minister, there was a debate; firstly, the Congress Party ridiculed it but, subsequently, they also joined the debate, and, the Prime Minister himself said that within 100 days, we would initiate steps to unearth the black money, to get back the black money from Swiss Banks and other tax heavens. Not even a word on it is mentioned by you. With regard to internal black money also, no concrete steps were suggested by you. That is another disappointment. Sir, the people thought that the lessons

learnt in the 1980s on deficit financing, which landed the country in a fiscal mess and eventually grew into a crisis of balance of payments in 1991, would be kept in mind while formulating our fiscal policies. That has not happened. We had a breakdown in 1991 and one of the reasons was fiscal mismanagement between 1986 and 1991. What was the deficit at that time, Sir? It was 7.7 per cent. Today, the combined deficit of the States and the Centre is going to cross more than 12 per cent. Sir, please remember, because of the crisis only, all political parties came together, and Parliament in its collective wisdom passed the FRBM Act in 2003. It was said, 'it is necessary for the country that the gross fiscal deficit as a proportion of the GDP should be brought down from 6.2 per cent in 2002 to 3 per cent in 2008. The revenue deficit must be eliminated by 31st March 2008. And a healthy surplus of revenue account must be built up.' That was the tone and tenor of debate at that time. What happened to that? It was a collective decision, not a decision of the BJP Government or anybody else. You seem to have given a go-by to that. Now the biggest challenge is the fiscal deficit as well as the revenue deficit. The revenue deficit is the difference between the revenue receipts and the revenue expenditure. Incredible as it may sound, the revenue deficit for 2009-10 is budgeted to go up to an astonishing 412 per cent from the estimated 70 per cent of the fiscal deficit of 2008-09 as against 41 per cent of 2007-08. This is the highest revenue deficit since the reform process began in 1991. I am quoting this from an editorial of an economic newspaper. You can say The Economic Times. If they are wrong, we will be happy. You can disprove us. How do you meet this? From domestic market, or by borrowing from oversees or by printing money. These are the three alternatives. If there is some other alternative, and if you can really bring it out, we will be more than happy. But each one of these three alternatives will have effect on interest rates. The revenue deficit does not result in creation of assets. It will add to the interest rate and repayment burden without creating a source of payment. Sir, someone asked, 'what is fiscal deficit?' One man said, 'fiscal deficit is, you borrow some money and purchase a house and live there.' He said, 'revenue deficit is you borrow money, eat, drink, be happy, and watch your midnight cinema.' The other day one of the valuable Cabinet colleagues suggested, to contain

population, it is better to watch cinema up to midnight.

Because going to cinema is not safer and it cost money. I do not want to score political points with anybody and do not want to get detracted also. Sir, it took us three years to get our revenue deficit from 4.39 per cent of the GDP in 2001 to 2.59 per cent of the GDP in 2005-06. Your fiscal plan suggests that it will bring down revenue deficit by the same margin within one year. How are you going to achieve this? Where is the magic wand? Please enlighten us also.

Agriculture, as I told you earlier, is the basic culture of our country. People in the rural areas are very, very unhappy. I am not talking about one Government. Massive suicides are taking place. There is migration taking place in the rural areas. People are leaving agriculture. If they will continue leave agriculture at this rate, what will happen to agriculture I am afraid? Sir, a politician's son wants to join politics. Many have come whether they have the capacity or not. A doctor's son wants to become a doctor. An actor's son, even if he is not good looking, is becoming an actor. A teacher's son also wants to become a teacher. A businessman's son wants to become a businessman. But no farmer wants his son to become a farmer. This is an irony. This really pains me. I come from a village. I feel proud that I am an agriculturist. I used to walk 3 km a day to go to school. I know the problems of the rural areas. Why are they not able to do justice to them? We have forgotten the recommendations of the Swaminathan Commission.

Sir, laborious efforts have been made by the Commission. They made a very good report after painstaking efforts. The Government did not even bother to inform us as to what action has been taken or what is the follow-up on the recommendations of the Swaminathan Commission. The hon. Finance Minister said that he was happy to announce that people who pay promptly will get one per cent interest exemption. It is very good. Sir, I salute you. But, what about the people who are not able to pay at all.

When people are not able to repay the loan, that's why they are committing suicides. If they are in a position to pay back the loan, then, there is no question of suicides or leaving agriculture. You should have taken the initiative and gone by the recommendations of the Swaminathan Commission and the requests of all the farmers'

organisations including your party people. Everybody said that interest rate for agriculture has to be brought down to four per cent. Some States are implementing it. In Karnataka, my Government is implementing it. The Andhra Pradesh Government is also trying to implement it. The Madhya Pradesh Government is also implementing it. In some States, it is three per cent. But, at the national level, you must think whether it is possible for the States to bear the expenditure. Can they repay or subsidise the money to the central bank? It is not possible. Then, you also said that you have raised credit limit to Rs.3,25,000 crores. Sir, we welcome it. But, at the same time, even the Radhakrishnan Committee report says that out of eleven crore farmers, not even 1è4th are getting institutional credit. That is the reality of the situation. People are borrowing from private sources. The Radhakrishnan Committee has also made a recommendation that we must cover as many areas as possible. The other day, the hon. Finance Minister said that he will open more branches and that the banks have been mandated. Sir, Rs.3, 25,000 crores is not a budgeted amount. This money is given by banks. They are performing their responsibility but, what is the relief that the Government is giving? If you are saying 'four per cent', then, you will be bearing the remaining thing. It was 16 per cent during your earlier regime. Shri Atal Bihari Vajpayeeji had brought it down to nine per cent and subsequently, to seven per cent. You are continuing with seven per cent. I am happy about it. But, at the same time, seven per cent will not hold good now with the rising prices and rising cost of agricultural inputs.

There is a need to have more dose of credit to the rural people. Also, taxation limit has to be brought down. There is a saying in Telugu. *Rythu lenide rajyam ledu.*

All the people sitting here including those sitting on the Congress benches have given speeches and come up to this place. But, what has happened? *Rythu lenide rajyam ledu.*

That means that if there is no farmer, then, there is no country. That is the translation of it. But, unfortunately, Sir, our investment in agriculture is going down. There is no mention of farm income insurance scheme. There is no mention of introducing a pension scheme for aged helpless farmers. Technology, productivity, remunerative price, crop diversification, etc. need special attention.

Enough money is not given to them. The allocation to irrigation sector is also too much. There is no stress on seed development or the availability of good seeds. These are the areas where I expected the Government to pay more attention.

A relook at the SEZs is also very much required. Some of the SEZs have done well. But, others have become real estate projects. We should never allow the private operator to convert the SEZ into a real estate proposition. Exports have gone up. I do agree, but, at the same time, we have to have a revisit and then, have a fresh look. Sir, about the fertiliser subsidy, the less said, the better.

Mr. Vivek Devrai gave history of 22 occasions on which the Prime Minister said that subsidy regime should be changed. Now, the Finance Minister, in his speech, said that he will also think about alternative methods including direct transfer of money and direct provision of subsidy to the farmers. Sir, when? This was said 23rd or 24th time. This has to be really addressed to. Then, the RBI should also focus on including food processing under the priority sector lending. Mega food projects which were initiated by us need to be expanded. Sir, the biggest issue, as I told you, is about the mismatch between WPI and CPI -- not the CPI of Mr. Raja, but the real CPI which is harassing us. It is the Consumer Price Index. He is a senior colleague. He has his own ideas. I salute him. He never changes parties. I am sure about it.

That is a weakness of the BJP and Communist people in this country. Some people ridicule you saying that you fellows stick to the same party, what is happening here, etc. But, we feel proud. We feel proud. Win and rule; something happens. It is not a Twenty 20 cricket match. You win and, then, roar; when you lose, then your effigy is burnt in the streets. That is what is happening in the cricket.. Sir, the common man is paying more because of this jugglery between WPA and, then, consumer price index.

Today, Sir, I request you to please-- I do not know who gets provisions at your house, the hon. Finance Minister. There must be somebody, family members or servants or somebody else; even you don't know that person. We don't have that much time. We may go to other market. We may not be able to go to this market, this vegetable market or that vegetable market. Wheat - it was Rs.9è-; today, it is Rs.17-Rs.23. Atta - it was Rs.10è-. Now, it is

Rs.18è-. Rice - it was Rs.10è-. Now, it is Rs.48è-. Sugar - it was Rs.14è-. Today, it is Rs.27è-.

This is not my figure. I was just carrying a clipping of a Congress supporting newspaper of Andhra Pradesh, the other day. Fortunately, they highlighted it as the lead story "*Sukkal* lo *Sakkara*" (TELUGU) .That is a reality, Sir. If you tell us, 'No, no, no. Diabetes is increasing. Reduce your consumption of sugar", Sir, Moong Dal - it was Rs.24 at that time. Now, it is Rs.64è-. Arhar Dal, Sir. This is a very, very protein food, according to the articles written by many newspapers. Many people were vegetarians or many were converted into 'vegetarian'. Doctors also told me that you have eaten sufficiently for this life--about non-vegetarian, go to vegetarian. That is the advice given to me. The Arhar Dal, Sir, what we call "kandi pappu", it is sold at Rs.80è- a kilo.

Sir, Rajmah, it was raised from Rs.28è- to Rs.60è- Mustard oil - Rs.30-Rs.35 to Rs.67è-. Milk - Rs.26; LPG cylinder - Rs.300è-; petrol - of course, Rs.44è- for that some international excuse! And cement - it was Rs.125è- during our regime. Today, it is Rs.245è-. I do not want to go further into gold, silver and all other items, they are not the issues .

But I thought price-rise also will grow by age, not at the alacrity of 100 per cent or 200 per cent! Vegetables - I need not say much. Sir, vegetables in my part of the country, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh, vegetable tomato is sold at 40 paise or Rs.one per basket, not a kilo. ...(Interruptions)... And, then, by the time it goes to Bangalore, and, then, comes to Delhi, it is Rs.16è-, Rs.20è- because it is perishable, and we do not have enough refrigeration system to transport those things. You have been talking about it, but you were not able to do enough; our Government also made efforts for preserving perishable items -cold storage chain, rural godowns chain.

We have to focus more on that and more and more incentives for food processing, for preservation of the perishable items have to be given; nobody is going to object. If you give concessions to some big, big people like branded jewellery, people may raise eyebrows. Bur if you give concessions to these food processing units, Sir, which will add to the assets and wealth, and also improve the health of agriculturists, nobody is going to raise any objection.

About NREGA, the hon. Minister said '144 per cent increase'. I am not able to understand that. I have been working out, calculating; I am not that much expert in Mathematics. Sir, the increase is only 6.4 per cent. If you go by the Revised Estimate, he said "From the present 45 days, it will be extended to 100 days." And you also said, "From Rs.80è-, because the prices have gone up, it will be enhanced to Rs.100è-." If you go by that calculation, the increase is 6.4 per cent. NREGA - lc lEOA?OOvksa ds fy, NREGA. NREGA is good for every purpose.

जब काम मिलेगा, NREGA में काम करेगा। बाद में क्या करेगा, मरेगा क्या 40–50 दिन के बाद क्या करना And are you creating assets? Sir, we must have a relook at it, and we are here to support you. This NREGA programme has to be replanned to see that it also helps to asset-creation, rather than just giving only wage employment temporarily.

I don't want to take the time of the House to explain what many people are doing because the Chair has given me some time. The time has been allotted. Sir, the CAG says out of 3.81 crore households listed under the Scheme, only 22 lakhs, that is, six per cent, are getting mandatory and legally available ten days. This is not my report. This is the report of the CAG.

The details about the success stories, list of beneficiaries, the list of lal card holders, the number of days they worked, the amount of money they got, etc., have to be exhibited publicly in every village. Make it mandatory. Some States are doing it. Namo Narain Meenaji is aware of it. Rajasthan has, to some extent, done it. I, as Minister for Rural Development, tried to ensure that process, but not met with much success because there was some resistance. But that has to be done. For JNNRUM, you had allocated Rs.23,548 crores. Do you know how much money was utilised? Only an amount of Rs.8,250 crores was utilised because matching grant was not available with many States. This is an area of concern. Two-thirds of the Central allocation were remained unutilised. What is the reason? This has to be studied. Regarding food security, the increase in the Budget is Rs.8,862 crores more than what has been spent last year.

Now, you are saying that a Food Security Act is going to come. Do you mean to tell us that the country has to wait for the Food

Security Act to come? Till such time will there be no rice at Rs.2 per kilogram? When are you going to start this? What is the finance provided for that? Our Chattisgarh Government is giving rice at Rs.2 per kilogram.

The Tamil Nadu Government is giving rice at Re.1 per kilogram. The Andhra Pradesh Government is also giving rice at a subsidised rate. The Karnataka Government is also giving rice at a subsidised rate. But the States' resources will be affected in the long term. This is the duty of the nation. Food is a fundamental right. I am happy that you are going to make the Food Security Act. You bring it at the earliest. But make provisions in the Budget so that the people get benefit. Don't ask them to wait. Under the Annapoorna and Antyodaya Yojanas people are getting more. But you are trying to reduce it. Under the Annapoorna Yojana we are giving 10 kilograms of rice free. What is going to happen to this scheme? Under Antyodaya, our Government was giving 35 kilograms of rice at Rs.2 per kilogram. Now you are increasing it to Rs.3 per kilogram and reducing it to 25 kilograms. Is it the concern for aam admi? आम नागरिक के लिए यह कदम आप उठा रहे हैं? क्या यही आपके मैनीफैस्टो में लिखा है? इसके बारे में सरकार के पास क्या समाधान है? सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मिल स्किम में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई। आपने जो फिगर पिछली बार दी थी उतना ही allocation है। आपने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस मुर्शिदाबाद और मलापुरम में extend करेंगे, हमें इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में सोचिए उसको आपने क्यों छोड़ दिया?

The Banaras Hindu University is also a prestigious institution. Why are you not establishing branches of the University? I think, the Madras High Court or some other judgment said that universities could not even establish branches. I don't know. Someone told me. I will be verifying it. If this is the case, then you are opening a new issue where there will be controversy. Tomorrow people will talk about the Banaras Hindu University. Then, regarding health, the total expenditure on health, as a proportion to the total Budget Expenditure, has declined from 2.11 per cent in 2007-08 to 1.97 per cent. I got the figures. I don't know whether the CMP, the Common

Minimum Programme, is there. Sitaram Yechuryji, is it there? I thought that the CPM is not there, but the CMP is there. So far as the textile sector is concerned, the Secretary said that 25 lakh jobs have been lost. What are the incentives you are planning to give? It is an important issue. The textile sector is one sector which provides jobs to 35 million people in this country. Please give them lower interest rates.

If you compare it with China, Bangladesh, Sir Lanka, South-East Asian countries, our interest rate or the cost of credit is high. This is what they are saying. I would like to the Finance Minister to look into it. I come to pharmaceutical industry. It also needs concrete steps. The indigenous medicine developers need to be given incentives. You have reduced import duty on cancer related medicines. That is not going to solve the problem because the Indian medicine is going to cost less than that medicine. So, please give money for R&D and also encourage the indigenous pharmaceutical sector in this country so that we, ourselves, are able to develop the medicines which are required for our people because we have huge population. I come to infrastructure. Infrastructure is one area which is neglected. I do not want to go into it.

My friend, Shri Arun Jaitley has talked about Golden Quadrilateral', North-South-East-West Corridor.What is the position today? I must also inform the House that the Golden Quadrilateral was started and then completed. Now it is coming up for up making or repairing after eight or nine years. That is not being done. This is an important aspect which has to be kept in mind. With regard to the National Highways, any negligence will be criminal in nature. The Railways are plagued with outdated technology. Average goods train's speed is 22 kilometres and of passenger train is 50 kilometres per hour now, in the 21st Century. The berths of various ports are overcharged. It takes 20 days in India; whereas, it takes a few hours in Singapore. The peak hour deficit of electricity is 13.8 per cent. The Prime Minister said that he would have a Committee. I am happy. The PMO said that they would monitor all the roads and other infrastructure projects. Last time, responsible people were not given this responsibility of managing these infrastructure projects. I do not want to go into the details because some of them are not here.

Secondly, you have to take care of the delays. The Commerce Minister, Shri Anand Sharma, said that there was huge improvement in the last one month and the decline has come down from 33 per cent to 29 pe r cent. He calls it huge. If it is one per cent decline, we can understand. The decline has come down from 33 per cent to 29 per cent. He is saying it huge. The export sector needs a major stimulus package from the Government. But there is no such provision in the Budget. Sir, oil exploration is another important aspect.

The Bay of Bengal has become the great new northern sea of Asia. The Government Departments should not quarrel over what is natural gas, what is mineral and what is this and what is that. We have to give more impetus to infrastructure. Now natural gas is also an important infrastructure in view of the problems we are facing. They have to be given the needed support, Sir. In regard to the IIFCL, the Finance Minister said that Rs. 1,00,000 crores would be provided by the IIFCL. I recall the earlier experience. The State Bank of India and the HDFC had earlier tried it, but they could not succeed. We all have seen that. I think certain norms have to be relaxed. I hope the Finance Minister would look into that. Another big disappointment, personally to me and to the countrymen and many hon. Members is, there is no mention about river-linking project. The Ganga-Cauveri is going to be a big boon to the entire country. Sir, Rs. 5,38,000 crores is not a big amount for a country like India. These rivers should be linked. You have to plan that. There is a problem of drinking water in India. People are saying that there are going to be water riots in future. We have to give top priority to the river-linking project.

I hope the Prime Minister and the Finance Minister would give needed attention to that. So far as production of power is concerned, we have to increase it. You can see what is happening in China. Power is a big problem in this country. I am not talking about political power, I am talking about other power. The real estate sector needs to be given more impetus. People expected the Government to increase the rebate on repayment of housing loan to, at least, 2.5 lakhs per annum on interest and on principal, from Rs. 1 lakh to Rs. 2 lakh. This has not happened.

The interest on housing loan should be brought down. In this

House I asked the Finance Minister, "Why are you increasing the rate?" He said, "No, no, already more than 40 per cent of the money is going to the housing sector. What is wrong in it?". It is a big problem for the people, the lower and the middle-class sections of our society.

Then, coming to disinvestments, you have talked less about disinvestments. That is okay. At the same time, what is the environment today? Are we in a position to attract the required response of the people, having bound itself by the illogical formulation of the remaining 51 per cent with the public sector? If monetary shareholdings of the public sector are to be off-loaded to the market without any sign of change in management and stake-holding of the public sector, the offer is going to be non-attractive to the investors.

How are you going to solve this problem? You are feeling shy to talk about disinvestments. I do not know the reason; now, Rajas and Yechuries are not there with you. Then, Sir, the internal security situation is disturbing. Kashmir is again boiling. The Separatist Forces are raising their ugly heads. What happened in Chhattisgarh yesterday? We hear from newspaper reports that an S.P. and 40 policemen have been killed. What is happening in different parts of the country? It is a matter of great concern, and the

Government needs to give more and more support to our security forces and also give moral support to them. We should not bend our head before the Separatist Forces which are trying to raise their ugly head once again in Kashmir. Kashmir is an integral part of India. There is no question of any compromise on Kashmir. That is the stand taken by the Indian Parliament, and we all stand by it. And the Government has to send such signals.

Then, coming to National Identity Card, I welcome the step. I hope that the initiative taken by the Finance Minister will bear fruit within a short time, and that it will be a reality.Now, coming to my suggestions, I would request the Government not to discriminate States. This is not a good thing. Please do not play politics with the security of the people. The Gujarat Control of Organised Crime Act (GUJCOCA) was sent to the Central Government, and the Government has simply sent it back to the State. You have a similar Act in Maharashtra. Simply because that State is ruled by Congress (I) and the other State is ruled by the BJP, you do not want such an

Act for the State of Gujarat. Why should you play politics on such a sensitive issue? I request the Central Government not to play politics on such a sensitive matter. There are complaints of discrimination. Karnataka is complaining that they have been discriminated with regard to even disbursement of the Natural Calamity Relief Fund. Madhya Pradesh feels the same way in the matter of coal allocations and power allocations. Orissa is also crying over the fact that they have not been given their due share.

The other States are saying that a step-motherly treatment is being shown to them. Andhra Pradesh is saying that a motherly treatment has not been shown with regard to various projects related to Railways. That is the position. I request the hon. Minister to pay attention to one particular project. Karnataka Government has set up a High-power Committee under Dr. Nanjundappa to assist the process of regional imbalances of the Gulbarga region, that is, Bellari, Raichur, Kopal, Gulbarga, Bidar, and parts of Hyderabad, which were earlier ruled by the Nizam. These are the most backward areas.

The Nanjundappa Committee has stated that 21 out of 39 backward parts of Karnataka lie in this area, and they have said that the Human Development Indicators are below the average. A total outlay of Rs.31,000 crores is required. The State cannot give that much money. A sum of Rs.2,489 crores were allocated in the last year's Budget. I would request the Centre to kindly understand the agony of the people of this region and then address the various issues.

Our Finance Minister is a well-learned person. He had presided over the Telengana Committee. What has happened to that Committee? There are issues relating to Telengana, Rayalaseema, Vidarbha, the KBK in Orissa, and that of Jammu versus the rest of the States. Such regional imbalances are not good for the unity of the country. Even when we take the Gorkha issue, pertaining to Darjeeling, there is a feeling of neglect.

So, we have to address these issues on priority. We must come out with a concrete plan. The Chief Minister of Bihar is saying that the land of Kautilya -- the hon. Finance Minister has also mentioned 'Kautilya' a number of times in his speech -- has not been given its due. Thirty lakh people have been displaced because of Kosi floods;

four hundred people are dead; 3,050 people are missing; 3 lakh houses have been destroyed. Now what is the assistance given to Bihar? There is no problem that you have given money to West Bengal. You must give them more, and we welcome it. We are happy that political differences did not come in the way. At the same time, the same thing should apply to Bihar also, which has faced such a big natural calamity. So, we must have a time-bound action plan to develop the backward regions of the country. Now, Sir, Karnataka wanted to have a hub of NSG. In spite of being a hub of I.T.s, an IIT has not been given to Karnataka. There is heart burning amongst the people of Karnataka on this issue. Now, they want to have a hub of the NSG unit. That also has not given to them.

Then, Sir, as regards Polavaram project of Andhra Pradesh, people expected that the REGP funds would be provided for this project, which is a multi-purpose project. This project would benefit lakhs of farmers in the area. There is no mention of it in the Budget.

Sir, I have two points more left. I am sorry that I have taken a little more time. I would then like to say about the Sri Lankan Tamils. Sir, when I speak about Sri Lankan Tamils, I speak with agony and pain. Going by reports that have emanated from Sri Lanka during the conflict, what has happened is horrible. The Tamilian people were put to torture, harassment and all that. Now, that is past history. You fight LTTE; we have no problem; we have no sympathy for LTTE which has taken the life of one of the leaders of our country.

In spite of political difference of opinion, you cannot accept this. Terrorism has no place. But, at the same time, in the name of crushing the LTTE, you have tried to displace the Tamilian population and harm their interests. Now, there is a fear. Mr. Rajapakse has made a commitment; there is a beautiful interview by C.N. Ram with the President of Sri Lanka; also, the other day, the Times of India carried a full page article about what is happening in Sri Lankan camps. I do not want to take the time and also do not want to place all of that on record in view of the sensitivity of the diplomatic relations we have with Sri Lanka. You have rightly announced a Rs. 500 crore-package but, please, see to it that it reaches the needy and there is no discrimination on the basis of race or religion or place, East or North, and see to it that Tamilian people also feel

that they are part of it. We are not in favour of an Eelam. I am happy that the Tamil Nadu Chief Minister has said that now Eelam is a matter of the past and the interests of the Tamilians are uppermost in the minds of everybody. That is fine.

We also have been saying that within the constitutional framework of Sri Lanka, the aspirations of the people of Tamil Nadu have to be respected. We have a special relationship with Sri Lanka. We must use our good offices to see to it that Sri Lanka adheres to the agreement that they have reached with us earlier, the 13th Amendment and, then, people are given relief without any discrimination.

The last point, Sir, is about the population control. The point is: 'Follow a non-coercive, incentive-based and gender-sensitive approach for population stabilisation'. Come with some concrete steps. This is my suggestion. Sir, some of the comments that I have made may appear to be very harsh. But I cannot help it because the situation is very harsh outside. People have been put to hardships. They are suffering. They are weeping. People are saying, "People are weeping and the Government is sleeping". They are not able to understand the concerns of the common man. I hope you understand it. You have no problems. You have no shackles. You have a comfortable majority. If you want to do something good, take our support for granted. There is no problem on that count.

We wish that you continue in power for five years. Do good things. But do not repeat what you have done in five years and make statements like the one the Finance Minister was making, 'there was tremendous improvement in the finances of the country'. We have all experienced what is 'tremendous'. I am thankful to the Chair and thankful to the House for giving me sufficient time and also for giving me a patient hearing without the usual disturbances.

सारांश

मैं बजट, 2009–10 पर चर्चा शुरू करते हुए प्रसन्न हूँ। मैं वित्त मंत्री जी द्वारा दिए गए अनेक प्रस्तावों से सहमति नहीं रखता हूँ। मैं निश्चित रूप से की गई कुछ पहलों का स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी देश के अत्यंत अनुभवी राजनीतिज्ञों में से एक हैं। देश प्रत्येक मोर्चे पर चुनौती का

सामना कर रहा है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कड़ी चुनौती का सामना कर रही है। चुनौती केवल वैश्विक वित्तीय संकट के कारण ही नहीं है, अपितु सरकार की निष्क्रियता के कारण भी है। पिछले पांच वर्षों में 'संप्रग' अपने वामपंथी मित्रों पर यह कहकर आरोप लगाता था कि वे बाधाएं खड़ी कर रहे हैं और हम निष्पादन नहीं कर सकते। अब आपके पास अपना बहुमत है। जब भी आवश्यक हो आपको कठोर निर्णय लेने में कोई रूकावट नहीं है। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैंः कीमतों में वृद्धि, आम आदमी की परेशानी, नौकरियों का न मिलना, बढती हुई बेरोजगारी, कृषि संकट और आर्थिक मंदी।

'नरेगा' के अंतर्गत हमें नौकरी नहीं अस्थायी मजदूरी मिल रही है। आपको नौकरी का आश्वासन नहीं दिया जाता। देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। यदि गैर–बजट मदों और राज्यों के घाटे को जोड़ा जाए तो संभावित वास्तविक घाटा 13–14 प्रतिशत से भी ऊपर होगा। देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले अधिकतम घाटा 7.7 प्रतिशत था। आप 1991 के परिणामों को जानते हैं जबकि हमें सोने को गिरवी रखना पड़ा था। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश को स्वपन बजटों के भ्रम में डालने के बाद, राजकोष को महाविपत्ति में डाल दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण ने इससे उबरने के दिशा–निर्देश दिये हैं। इसने कतिपय ठोस सुझाव दिए हैं। इसने कुछ क्षेत्रों की पहचान की है जहां प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। इसने कुछ क्षेत्रों की भी पहचान की है जहां सरकार द्वारा निवेश किए जाने की आवश्यकता है। सामान्यतया वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा दी गई सलाह से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और जहां भी आवश्यक हो कुछ कठोर निर्णय लेते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश इस समय ऐसा नहीं हुआ है। इसमें वित्तीय समझा, खाद्य सुरक्षा, या सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के लिए कोई लक्ष्य 200 निर्धारित नहीं किया गया है। बजट अवास्तविक है, अपारदर्शी है और यह अर्थव्यवस्था में कोई हलचल पैदा करने वाला नहीं है। यह पिछली सरकारों द्वारा आर्थिक कुप्रबंध का स्पष्ट उदाहरण है। पिछले पांच वर्षों में वित्तीय प्रबंध दयनीय रहा है।

अब सरकार, अपनी कुप्रबंध के परिणाम पर पर्दा डालने के लिए एक बहाने के रूप में, 'अंतर्राष्ट्रीय मंदी' शब्द का प्रयोग कर रही है। वर्तमान आर्थिक मंदी में कोई भी वित्त मंत्री से किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करता। मैं मौजूदा वित्त मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं

ठहराता। परंतु यह सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है।

आप पूर्ववर्ती सरकार पर यह कहकर दोषारोपण नहीं कर सकते कि यह अव्यवस्था में थी और हमने पांच वर्षों में हमने बहुत अच्छा निष्पादन करने की कोशिश की और हम असफल हो गये हैं। जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी वित्त मंत्री थे तो मुद्रास्फीति की दर घटकर 4.2 प्रतिशत हो गयी। 2003–04 के दौरान राजग के शासन के अंतिम 3 वर्षों के दौरान यह मुद्रास्फीति की दर घटकर 4.2 प्रतिशत हो गयी थी। वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण में इसे स्वीकार किया गया। हमें इस बात की खुशी है कि भारत 10,00000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का बजट रख सकता है और जिसे हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। परंतु उसी समय इसमें से हम गैर योजना राजस्व व्यय पर 6,18,834 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। यदि सरकार 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण ले रही है तो बैंकों पर भार पड़ेगा। गैर–सरकारी कर्जदारों का क्या होगा?

माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बैठक की और लोगों को यह आश्वासन दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। गैर–सरकारी लोगों को भी पैसा मिलेगा कहां से? निजी क्षेत्र के लि ब्याज दरें बढ़ जायेंगी। पिछले साल में 2009–10 बजट में प्रस्तावित एक लाख बीस हजार करोड़ के अतिरिक्त व्यय में से 44 हजार करोड़ रुपए छठे वेतन आयोग पर खर्च हो रहे हैं। ब्याज भुगतान, रक्षा, राजसहायता, वेतन और पेंशन के कारण विशाल व्यय में वृद्धि हो गयी। जनता वित्त मंत्री जी से ऐसी उम्मीद करती है कि वो राष्ट्र को विश्वास में लेकर चलेंगे, अवसर का उपयोग करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा दी गई चेतावनी और सलाह को ध्यान में रखेंगे। तत्पश्चात् 201 राष्ट्र के समक्ष उन दिशा निर्देशों को अनुपालन के लिए रखेंगे। यह बहुत निराशापूर्ण है। कुछ विशेषज्ञ यह चेतावनी दे रहे हैं कि देश संकटपूर्ण स्थिति की ओर बढ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा न हो। परंतु उसी समय ऐसे संकेत हैं कि स्थिति और खराब होती जायेंगी। उन्होंने इस बात को रेखांकित नहीं किया है कि बजट किस प्रकार से घाटे को ध्यान में रखेगा। पहले दो महीनों में, केन्द्र और राज्यों में 1,81691 करोड़ रुपए का ऋण लिया जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में लिए गए ऋण से 42 प्रतिशत अधिक है।

वित्त मंत्री द्वारा अपनाई गयी पारंपरिक पहुंच सुधारों को आगे बढाने की है। ताकि आर्थिक गतिविधि पैदा की जा सके। परंतु इस बजट में वित्त मंत्री ने सुधारों को पूर्णतः छोड दिया है। पूर्ववर्ती वित्त मंत्री और 'संप्रग' हमेशा

आर्थिक सुधारों की बात करते रहे हैं। आजादी से लेकर अब तक आप सत्ता में बहुत वर्षों तक रहें। कांग्रेस ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया। हम पांच से छह वर्षों तक के सत्ता में थे। परंतु क्या वह लंबी अवधि गरीबी को पर्याप्त रूप से घटाने के लिए काफी नहीं थी? क्या वह बेरोजगारी की समस्या को हल करने के पर्याप्त नहीं थी? क्या वह क्षेत्रीय असंतुलनों की समस्या को हल के लिए पर्याप्त नहीं थी? क्या वह सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी? हमें सार्वजनिक क्षेत्र को भी समय देना चाहिए। इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। हम सार्वजनिक क्षेत्र के विरूद्ध नहीं है। परंतु एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू ने उस समय उद्योगों को स्थापित करने की समझ दिखायी थी। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न उद्योगों को स्थापित किया था। यह एक अच्छी चीज है, हम इसके विरूद्ध नहीं है। परंतु आज निजी क्षेत्र एक बड़े पैमाने पर आ रहा है जिसमें परियोजनाओं में वित्तपोषण के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आ रही है, तो सरकार को परेशान होने की क्या आवश्यकता है? यह एक अन्य महत्वपूर्ण बात है। विद्युत, सड़क, जल, सिंचाई, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, के लिए हम इन वर्षों में क्या कर पाये हैं, हम अपने लक्ष्यों को पूरा क्यों नहीं कर पाये हैं? आपको इसका समाधान करना होगा।

योजना आयोग का कहना है कि देश के 27 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। मैं इन आंकड़ों के बारे में वित्त मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा। आप ब्रांड वाले जेवरात को प्राथमिकता दे रहे हैं। मुळो नहीं लगता कि इस छूट से आम आदमी को कोई फायदा होगा। आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय पिछले पांच वर्षों में 7.3 प्रतिशत से घटकर 4.5 प्रतिशत रह गई है। देश को व्यवसाय क्षेत्र और सरकार से बड़ी मात्रा में निवेश की जरूरत है।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मुझे उम्मीद है कि आप इस योजना के लिए और ज्यादा धन देंगे। हमें ग्रामीण सड़कों को और अधिक प्राथमिकता देनी होगी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभावों से निपटने के लिए हमने टैक्स कटौती और खर्च में वृद्धि के एक विवेकसम्मत संयोजन की उम्मीद की थी ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। अब अचानक ही आपका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की वजह से हालात बदल गए हैं। प्रत्यक्ष कर छूट के मामले में भी अत्यधिक निराशा हुई है। आपने फ्रिंज बेनिफिट कर हटा दिया

है। यहां कुछ संदेह पैदा हो गया है। अब भविष्य में कर्मचारी को कर अदा करना होगा। मुळो खुशी होगी अगर वित्त मंत्री अपने उत्तर के दौरान इस मुद्दे को स्पष्ट करें। लोगों को आशा थी कि अचल संपत्ति को किराये पर देने के संबंध में सेवा कर समाप्त कर दिया जायेगा और लोगों ने यह भी सोचा था कि आप पर्यटन को कुछ प्रोत्साहन और होटलों आदि के लिए करावकाश देंगे। 'एक रैंक एक पेंशन' के बारे में भी निराशा हुई है।

आंतरिक काले धन के संबंध में भी कोई ठोस सुझाव नहीं दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे की है। राजस्व घाटे से परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं हो पाता। इससे किसी भुगतानस्रोत के सृजित हुए बिना ही ब्याज दर और वापसी अदायगी का बोझ बढ जायेगा। कृषि हमारे देश की मूलभूत संस्कृति है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत अप्रसन्न हैं। बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देशान्तरण के हालात पैदा हो रहे हैं। लोग कृषि को छोड़ते जा रहे हैं। कोई भी किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने। इससे वास्तव में मुझे तकलीफ हुई है। हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को भुला 203 दिया है। आयोग द्वारा कठिन प्रयास किए गए हैं। उन्होंने अथक प्रयासों के बाद एक अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। सरकार ने हमें यह भी बताने की जरूरत नहीं समझी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है। आपको इस मामले में पहल करनी चाहिए थी। सबने कहा है कि कृषि के संबंध मे ब्याज की दर घटाकर 4 प्रतिशत पर लानी होगी। कर्नाटक इसे कार्यान्वित कर रहा है। आंध्र प्रदेश भी ऐसा करने का कोशिश कर रहा है। राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 करोड़ किसानों में से एक चौथाई किसानों को भी संस्थागत ऋण नहीं मिल रहा है। यह स्थिति की वास्तविकता है। लोग निजी स्रोतों से उधार ले रहे हैं। ग्रामीण लोगों को और अधिक धनराशियां उधार दिए जाने की जरूरत है तथा कराधान सीमा को भी कम करना होगा। दुर्भाग्यवश कृषि में हमारा निवेश कम होता जा रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर भी फिर से नजर डालने की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निजी प्रचालक विशेष आर्थिक क्षेत्रों को 'रियल एस्टेट' योजना में बदल दें। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच तारतम्य न होना सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी की वजह से आम आदमी को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें बढ रही है। खाद्य संसाधनों और खराब होनी वाली चीजों

के परिरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने होंगे। 'नरेगा' कार्यक्रम को फिर से व्यवस्थित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह केवल स्थायी रूप से रोजगार देने की बजाय परिसम्पत्तियों के सृजन में भी मददगार साबित हो।

जे.एन.एन.आर.यू.एम. के लिए आपने 23.548 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। यह एक चिंता का विषय है। खाद्य एक मौलिक अधिकार है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने वाले हैं। आप इसे शीघ्र से शीघ्र लेकर आएं। किन्तु बजट में प्रावधान करने होंगे ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। स्वास्थ्य पर होने वाला कुल खर्च, कुल बजट खर्च के अनुपात के रूप में 2.11 प्रतिशत से घटकर 1.97 प्रतिशत रह गया है। यह कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद का 2–3 प्रतिशत दिया जायेगा। 'लाडली लक्ष्मी योजना' और 'आरोग्यश्री' महत्वपूर्ण योजनाएं हैं क्योंकि इनमें बालिकाओं और ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य को शामिल किया गया है।

वस्त्र उद्योग क्षेत्र इस देश में 35 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कृपया उनके लिए ब्याज दरों में कमी कर दीजिए। फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए कतिपय ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस देश में स्वदेशी फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि वे सभी सड़कों और अवसंरचना संबंधी अन्य परियोजनाओं की निगरानी करेंगे। निर्यात क्षेत्र के लिए एक बड़े प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता है किंतु बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तेल अन्वेषण एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। हमारे समक्ष उपस्थित समस्याओं को देखते हुए अब प्राकृतिक गैस भी एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है। उन्हें आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए।

यह देखकर निराशा हुई कि नदियों को जोड़ने की परियोजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। गंगा–कावेरी नदियों को जोड़ा जाना चाहिए। भारत में पेय जल की भी समस्या है। मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इस ओर ध्यान देंगे। हमें विद्युत उत्पादन को भी बढाने की आवश्यकता है। हमारे समाज के निम्न तथा मध्य वर्गों को राहत देने के लिए गृह ऋण पर ब्याज को कम किया जाना चाहिए।

आंतरिक सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। यह गंभीर चिंता का विषय है और सरकार द्वारा हमारे सुरक्षा बलों को और अधिक सहायता देने की

आवश्यकता है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर के संबंध में किसी प्रकार के समझौते का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारतीय संसद ने यह निर्णय लिया है और हम सभी इसका समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाया जाना स्वागत योग्य कदम है। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही ऐसा संभव हो पाएगा।

राज्यों ने भेदभाव किए जाने की कुछ शिकायतें की हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्यों के साथ भेदभाव न किया जाय और संवेदनशील मामलों पर कोई राजनीति न की जाए। बेलारी, रायचूर, कोपल, गुलबर्गा और बिदर कर्णाटक तथा हैदराबाद राज्यों के सबसे पिछड़े इलाके हैं। मैं केन्द्र से इस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को समझने तथा उनके विभिन्न मसलों का समाधान करने की प्रार्थना करता हूं। क्षेत्रीय असंतुलन देश की एकता की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है। हमें ऐसे मसलों पर सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए। देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए हमारे पास समयबद्ध कार्य–योजना होनी चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना एक बहुउद्देश्य"य परियोजना है जिससे इस क्षेत्र के लाखों किसानों को लाभ होगा। बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मैं वेदना और पीड़ा के साथ श्रीलंका के तमिलों की बात करना चाहता हूं। आपने उनके लिए 500 करोड़ रूपए के पैकेज की घोषणा करके अच्छा किया है किंतु आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह धन जरूरतमंदों तक पहुंचे और जाति अथवा धर्म या स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाय। अंत में, मैं जनसंख्या नियंत्रण के विषय में कुछ ठोस कदम उठाने की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

Our Budgets have become, another dhobhi list

-Arun Shourie

Mr. Deputy Chairman, Sir, we have had very authoritative interventions by Dr. Rangarajan, by my dear and long-standing friend Shri N.K. Singh. We have had important and constructive suggestions from the representatives of industry and other interests. I would come back to these points to add to some of them and differ from some of them. But I first want to start with paying, really, a compliment and congratulations from the bottom of my heart to the Finance Minister and I hope that the Minister of State will convey that to him for a matter which is not mentioned in the budget but which falls in his purview.

Sir, as you know, when the President's Address was being discussed, I had drawn the attention of the House to many things, to dangers from many quarters. As a symptom of that I had drawn the attention of the House to the fact that China had blocked a loan to India from the Asian Development Bank. Though the loan was almost four billion dollars, but a very small component of three-four million dollars related to Arunachal Pradesh. They said, "This is our territory. No loan to India can go on that". This is a very serious development. It was in continuation of their policy. But the Finance Minister, the team in the External Affairs Ministry and in the Prime Minister's Office, they took a clear and firm stand in this regard. China persisted with this. For the first time, in the history of the Asian Development Bank, they insisted that there will be a vote in the Board of the Asian Development Bank. India stood firm. It mobilised support from different quarters, including the United

States. And the result was, the Board, with one dissent that of China, voted that the loan would be given to India. This is a single achievement. It is the first time that China has suffered a setback. I can say from personal knowledge, having travelled to that region, that it has been noticed all over East Asia and South-East Asia. So, irrespective of any differences that anyone of us may have, I compliment the Finance Minister and his other colleagues in this regard. I hope the same clear and firm stand will be taken in regard to the pressures which are being put, which he knows, in regard to Kashmir, in regard to assumption of dialogue with Pakistan without precondition, in regard to WTO that Arunji had mentioned in his intervention, the first time, in regard to the various treaties like NPT and others. And, much will depend upon the Finance Minister personally because I know the role that he played in regard to Siachen. That is one point.

The second point is, as Dr. Rangarajan was mentioning, and Shri N.K. Singh was mentioning, we all recognise that the Budget has had to be prepared in difficult circumstances and has had to be a balancing act. All of us recognise that. But, as Shri N.K. Singh also emphasised, much of this difficulty has been created. It is a self-created one that because of the stoppage of reforms, a complete paralysis of reforms for five years, the momentum slowed down. As people, like me, had pointed out, which Shri N.K. Singh has very well documented today, that when the index of industrial production was at its peak, it shows that a year before this crisis, jobs had already started getting lost in the textiles sector. By April, 2008, twenty-five lakh jobs had already been lost, according to official statements of the Government. And that was the real reason for the difficulties that came. On top of that, there was the global slowdown; therefore, the exports were slowing down. And revenues suddenly plummeted. We used to have a growth of almost 40 per cent in direct tax collections. That started plummeting. That would have led to the deficit. But the real contribution to the deficit, I should say, as has been mentioned by Dr. Rangarajan just now, has been that current expenditure has really not grown; it has gone out of control. This is a fact, and all these in the name of inclusive growth! I shall come to this point whether there is substance in that, or, whether we are just throwing money and saying that we are

doing this for inclusive growth. In spite of these circumstances, I am very happy that, at least, a few steps have been taken towards tax reforms. As Dr. Rangarajan just now mentioned, it is primarily an Expenditure Budget, and, even on tax reforms, there is no great architecture or vision that has become evident. But, at least, a few irritants, which were continued out of some sort of obstinate determination in regard to fringe benefit tax and others, have been removed. It is good that the Commodity Transactions Tax, which has actually never been made operational, has also been withdrawn. Both had smelt of the Inspector Raj being re-introduced.

There is a new Direct Tax Code to come within 45 days, service tax being extended to lawyers, the ten per cent surcharge being reduced and the Goods and Services Tax on schedule. Sir, there is a point in which I would like to second the appeal that Dr.Abhishek Singhvi made, and that is an appeal from all of us to all political parties. Everybody is in office in some State or the other, and he is right that it would not be correct for any one of us to delay things. It is true that the GST should not be half-baked or ill prepared. But a year is a long time for a country to think, for even to come to a consensus on these matters! I am sure, two weeks of concentrated work on this by distinguished people will leave almost no questions unanswered. It may leave out questions where negotiated solutions are not possible. But, at least, a clarity on the options should be there, and we should all co-operate in this regard so that everything that people want would come out, and we would continue to move on tax reforms. So, I second that particular appeal.

Sir, there are many other special measures that I found commendable, and I do not want to take your time on this. This threshold of non-promoter holding is a very good thing. The Assistance, that is being announced for the Infrastructure Finance Corporation, is also a very good thing. But the problem really is not in the specific measures because, after all, this Budget is a continuation of the Government which has been there for five years. So much work has gone on as regards the other steps that could be taken for an overall architecture for new tax regimes. But we do not find any trace of that at all. And, the Budget has been, as unfortunately, our Budgets and Addresses from the Red Fort and the Address of the President have become, another dhobhi list.

So many shirts, so many shorts, so many kurta-pyjamas! That is all. And it is this architecture, this vision, that is required, specially at a time like this when the country was seeing that it was in difficulties and, therefore, it needed what Dr. Rangarajan just now called, a 'roadmap', not just on taxation, not just on deficit, but on the general economic policy and reforms in this regard. I cannot imagine now what the difficulty and the constraint was because the difficulty and the constraint have been, for the time being, sort of waived by the people. मगर इसमें एक गफलत है, आप तो आलिम हैं, आपको याद है कि difficulty अब इनके अंदर है। गफलत यह है कि – 'जब तूफां में हो कश्ती, तब सब कोईसहाय' .- everybody can help you and save you, when your boat is in the storm -- 'जब कश्ती में हो तूफां, तो कौन सहाय'। So, the paralysis within the ruling party in this regard to reforms is what the problem is now.

That is why... it will all be clear व्योंकि constraint तो है नहीं। आप भी कहते हो कि mandate भी है, that will be very good. But on matters like labour, on matters like execution of infrastructure projects, on energy, on reforms in the coal sector, on open access to power, on distributed generation, all these things have been listed by Government reports themselves. But we find no indication that they are being brought forward in that respect.

Sir, there are only two reforms which are mentioned. Because this has not come up in other speeches, I will take you through the paralysis which characterizes this Budget and the functioning of the Government which I sincerely hope we will get out of. One is in paragraph 35. This is on POL pricing and subsidy. I will just read it out now. Sir, you know what happened last year; because administrative price mechanism had been sort of brought back and Ministries had started fixing prices again, the Chairman of the largest oil company in India, a Government officer, had to say in public that if within thirty days, the Government did not change the prices, he would not have one rupee to import more oil. That was what the situation had come to. And a loss of about Rs.40,000 crores had been inflicted on those governmental companies. What is the solution? "It is important to recognize that almost three-quarters of our oil consumption is made through imports. Domestic prices of petrol and diesel have to be broadly in sync with global prices of

these items". So, what is the remedy? "Government will set up an expert group to advise on a viable and sustainable system". Now, this expert group will be the fifth group, the fifth committee, commission and expert group, in the last five years, for the same thing; there was the Lahiri Committee in 2004; then, the entire working group on integrated energy policy, set up by the Planning Commission in 2005; the Rangarajan Committee in 2006; and the B.K. Chaturvedi Committee in June, 2008. Just see the Budget of 2005-06 of Chidambaram. He says, "As far as petroleum products are concerned, the Government has received the recommendations of the Lahiri Committee and appropriate decisions have been taken" -- 'have been taken' -- "to which I shall refer to in Part B". You will not find them in Part B. Then, in the next year, in 2006-07, he says, "My Ministry has held extensive discussions with stakeholders on three major subsidies, mainly, food, fertilizer and petroleum. "We have also sought the views of the general public." When you can't do something, seek views. "...Working Groups, Committees have gone into the question of fertilizer and petroleum subsidies, the latest being Dr. C. Rangarajan Committee.

I would urge Members to help the Government to evolve a consensus on the issue of subsidy." Then, in the Eleventh Plan the same thing was said. Now, why does this not happen? I don't want to cast any aspersion, and I am all, as you know, an advocate of vigorous private sector, vigorous and efficient Government, vigorous Government sector so that you can all have competition and prices come down and efficiency comes up. Why does this not happen on POL? Sir, there is a very good passage by the Commission headed by the Prime Minister, i.e., the Planning Commission. This is the Mid-Term Appraisal of the Tenth Five Year Plan put out by the Planning Commission in 2005. They say, 'Why does this not happen?' You find the same paralysis continuing now because you have to have another expert group. He says further, "The current pricing mechanism uses the import parity pricing..." You don't have to go into that. "...even for products in which India is the net exporter." I don't want to say who is exporting. "This provides higher margins to the refiners. Economic rationality suggests that the trade parity should be the norm for pricing instead of import parity. Moreover, Customs Duty on crude oil is five per cent, while the average duty

on petroleum products is ten per cent. This further increases the refinery margin." Then, the normative transportation is fixed, and he says, "For this reason, so as to help the public sector companies, but private sector refineries are following the same methodology for building up prices for their products." Then, he gives another feature of this pricing and then says, "This ensures even larger benefits for more efficient private refineries." So, you really have not just a paralysis within political parties or outsiders, but you have other interests coming into rational policies being introduced. And, therefore, what do we do? We set up expert groups, as we have done again, and we remain exactly where we have remained for the last ten years on this matter.

Sir, the second reform, the only other reform that is mentioned here is fertiliser subsidy. Sir, you just see again in paragraph 34 as to what it says. There are two lessons in this which you will see, I hope the Minister of State will notice, as to how one part of the Finance Ministry does not seem to know what the other part of the Ministry has done or is doing. It says, in paragraph 34, "In the context of the nation's food security, the declining response of agricultural fertiliser usage in the country is a matter of concern." Why? It is because we subsidise only nitrogenous fertiliser and this leads to imbalanced use of fertilisers in phosphates and potashic fertilisers, and that is leading to deteriorating in our soil. "To ensure balanced application of fertilisers, the Government intends to move forward to a nutrient based subsidy regime instead of the current product pricing regime. In due course, it is also intended to move to a system of direct transfer of subsidy to farmer." Now, Sir, if you see this is what we are being told today and this has been hailed as a great advanced scheme that, at last, we are going to a nutrient based subsidy regime. Now, if you see the Mid-Term Appraisal of the Tenth Plan put out four years ago, they say the same sentences that 'productivity is going down, and we are unable to do this because we are giving fertilisers in an imbalanced way. Continuation of the subsidy on urea while de-controlling PNK fertilisers further adds to the inadvertent promotion of imbalance in fertiliser use. One of the proven and well-documented reasons for stagnation in the productivity and production growth rates since the early 1990s is the unbalanced use of fertilisers."

Then he says, "In the Eleventh Plan approved under the chairmanship of the Prime Minister...." again, they say, "...soil degradation through the use of agrochemicals is a serious issue that needs to be addressed. Imbalanced use of chemicals and fertilizers is doing this." The reason they give is that the present system of fertilizer subsidy is irrational and has become counterproductive. All these members, including the present Finance Minister, all of them, are endorsing this. There are long passages and I don't want to take your time to say that this is the problem and it needs to be addressed in an urgent manner. Mr. Chidambaram first in his Budget of 2007-08 says, "It is a serious problem. While fertilizers should indeed be subsidised, we must find an alternative method of delivering the subsidy to the farmers...." This is exactly what the present Finance Minister has said, "...We are going to do in due course. The fertilizer industry has agreed to work with the Department of Fertilizers to conduct a study and find a solution. Based on the report, the Government intends to implement a pilot programme in at least one district in each State in 2007-08. In regard to the implementation of the Budget The problem is that you are continuing to make the same promises, which you have not been implementing at all. Again, they are saying that this is the reform.

The fact that the same promises are continuing to be made and are not implemented is a reflection of the fact that we are not proceeding as we should be doing. And that is one of the problems as identified by the Government report itself that the economic progress has been brought down to a slowdown, as Mr. N.K. Singh was just saying. This is the reason. So, you see the same thing happening in the 2008-09 implementation of Budget announcements and he said that the modalities are being worked. Now, once again we are told that this will be done in due course. Dr. Swaminathan has recommended these things, everybody has recommended. And for 15 to 2o years and certainly in the last five years there has just been a repetition of all this.

That is one point. But there is a second point by which I will come to your Budget of 2009-10 and on which you are very keen.

To ensure the balance application of fertilizers..",-- Mr. Deputy Chairman, Sir, this is a very interesting thing, the second aspect of this matter from the Budget of this year -- "...the Government intends

to move towards a nutrient based subsidy regime."

What does your Economic Survey laid in the same House by the same Finance Minister say this year? It says that it has already been done. It says, in addition, due to the implementation of the nutrient based subsidy pricing, prices of various complex fertilisers were reduced by 18 per cent on an average. कुछ पता भी है, एक तरफ आप कह रहे हो इंटेंड्स, अब बोलिए साहब, आप ही का बजट है इसी साल का। इसी साल की इकॉनोमिक सर्वे है, तीन दिन पहले दी गई।

Sir, but hope never dies. Hope is eternal. सर, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, The Government has taken various policy initiatives for the fertilizer sector. These cover pricing policy for indigenous urea, new investments in the urea sector, nutrient based pricing and production and availability of fortified and quoted fertilizers. Sir, the point that I was making was, that, on the only two reforms that are mentioned on POL, there is no progress. This is another fifth committee in five years. On fertilizer subsidy intentions for the future and we get nowhere at all. One part of the Ministry is not knowing what the other part is doing. Now, Sir, this characterises other aspects also and I will take up two examples from the current Budget.

One is power. Everybody has said on the shortage of energy and on various matters. Now, Sir, in case there is some impatience you should please look at paragraph 24, I am referring to that. Sir, in power the problem is that, we have set up a target of 78,000 megawatts for the Eleventh Plan. We are now going to be near the middle of the Eleventh Plan. How much have we achieved of 78,000? It is 13,000. Now, the reason for that is, you require almost 10-12 lakh crores in this sector against this because of profligate expenditure on so-called inclusive growth. We will not have half of this amount with the power sector and the result of that is, we will not get even 40,000 additional megawatts this year and the typical point and the point that illustrates it is in paragraph 24. It is called the Accelerated Power Development and Reform Programme. Sir, the Eleventh Plan said that this is one of the main challenges facing us.

This programme is not about generation. This programme is about subtransmission and distribution, i.e. transmission within States and further distribution. Here, just see what the paragraph says.

This is crucial because you have to reduce T&D losses from 35 per cent to 15 per cent as the Expenditure Budget presented now this year says in volume 2, page 182 of this Budget. 'To do this you require massive investments and this is an important programme.' Mr. Pranab Mukherjee said the Accelerated Power Development and Reform Programme is important for reducing the gap between power, demand and supply. I propose to increase the allocation for this scheme to Rs. 2080 crores, a steep increase of 160 per cent. It seems very impressive till you realise that what is actually required is 16,000 to 20,000 crores per year and that is why the things will continue exactly the same way. Even at the cost of irritating some Members I would remind you that in the previous Budget three years ago, we were told that the details of this scheme had been worked out. A national fund for Transmission and Distribution Reform is now to be contemplated. The details of the scheme will be worked out and announced very soon.

Then, you see what was said about this promise in the Implementation of the Budget Announcements of the Interim Budget that Mr. Pranab Mukherjee just presented in February, 2009. It says that sanction has been given. A Steering Committee has been set up. A nodal agency has been set up. The nodal agency has set up a process consultant. A process consultant is working on the empanelment of IT consultants. A quadripartite implementation agreement has been drafted. What about that fund which was to come very soon? सर, यह अकबर इलाहाबादी का couplet है। प्लेटों की आवाज़ आती रहती है। प्लेटों के आने की आवाज़ आती रहती है, कांटे–छुरियों की आवाज़ आती रहती है, मगर खाना नहीं आता। सर, यही हालत है। अच्छा अब आप देखिए, इन्होंने कहा कि फंड होगा, जल्दी बनेगा, अनाउंस जल्दी किया जाएगा। If you see the February document, what did it say about the National Electricity Fund? It says that a Committee under the Chairmanship of Member (Power) i.e., from the Planning Commission, has been constituted by the Planning Commission to consider various aspects of establishing a National Electricity Fund. A Committee has been set up. So, what did the Committee do? The Committee has decided to form a Sub-Committee under the Chairmanship of the Secretary, Power, to make recommendations on issues relating to operationalisation of the National Electricity

Fund. The matter is currently under examination and it continues -- I had checked it -- till last evening. This is the real problem. This is the reason for keeping tabs on what is promised from time to time. The House should not lose sight of that. I tell you that where the matter concerns about doing something, it does not get done. But, where the matter relates only to sending money to somebody else, that is done. That is shown as achievement.

The hon. Prime Minister has said it many times. Shri Chidambaram has said it -- not outlays but outcomes -- innumerable times. Actually, that culture is continuing exactly as it is in regard to employment schemes and in regard to everything else. A single example has mentioned here as an achievement. It is with regard to the Rajiv Gandhi Grameen Vidyudikaran Yojna. The target was to provide electricity to 2,35,000 villages. Of which, actually speaking, only 54,000 villages have been electrified, as reported by Shri Pranab Mukherjee's document of February, 2009. And, out of 7.8 crore households, which were to be provided electricity, only 43 lakh households have been given electricity! This is the problem.

Once we had told in this House that Ministries have been instructed to prepare Outcome Budgets. I don't know what has happened to that. That was there in the Budget Speech. Sherlock Homes used to say, 'there is a dog that did not bark.' We should look at that. For that reason, all of us who have got this Budget papers, the first paper is this. This is the List of Documents of Budget for 2009-10. It had 13 items. But, one item was missing. It is the Implementation of Budget Announcements. In every Budget, Mr. Chidambaram had a foreword to that document saying, 'this document has been introduced to ensure transparency and accountability and whatever promises we made we will report next year what we have done on that.' That is the only thing that is missing. How? Is it that accountability and transparency have been completely ensured; or that, that document was not doing that job; or, that document was proving an embarrassment because some of us were reading it? Sir, it is the same thing in regard to this great promise of the Food Security Act also. Everybody wants it.

Everybody wants the hunger to be abolished. But the way to do that has been given by some of the great experts, like, Dr. Swaminathan, who are honoured and listened to all over the world.

How to increase production? How to focus on farmers with less than two acres of land?

How to give balanced nutrients, not just these three fertilizers? We don't do that. But we just go on passing resolutions, go on having higher and higher targets. Goliath had referred to the Indian planning, saying that it indulges in therapeutic targetry. For therapy purposes, we raise the target. So, therapeutic legislations are also there. But the fact to be remembered is that the real problem is not being addressed to. It has been addressed to in every Budget. Today, already, 316 million people are covered by the Pood Distribution System. 316 million! And, as you all know, they are given 35 kg of foodgrains to the BPL families, antayodoya families, and so on. And, yet, despite covering 316 million people under the Public Distribution System, we are number 66 in the global hunger index. And, Sir, it will astonish you to learn who is above us. Albania is above us, Turkmenistan is above us, El Salvador, Gabon, Guyana, Honduras, Dominican Republic, Magnolia, Nicaragua, Lesotho, Namibia, Guatemala, Senegal, Uganda, all failed States, Swaziland, Sudan, Nepal, Djibouti, Guinea, Pakistan, Malawi, Rwanda, Cambodia. The best performing State, in India, on hunger is Punjab. And, that would be 34th in this

Sir, the point that I was making was that instead of going on passing more and more laws we should really be attending to the things like the Public Distribution System because, again, the law may be passed, but we will have to do the same thing.

That's why I would be enthused, about these allocations and these Acts, only when some concrete steps are visible in the field on improvement of delivery system, of which this Budget also talks.

Sir, because great authoritative people, like, Dr. Rangarajan, Shri N.K. Singh and others have spoken on the issue of deficit, I won't take much of your time on that. But I would like to make two points on that.

One, the claim is a surprising claim in the Budget. That is, if you see, it says, "To counter the negative fallout of the global slowdown in the economy, we have brought about this deficit". The difference between the actuals of 2007-08 and 2008-09 constituted the total fiscal stimulus.

Shri Pranab Mukherjee says, "This fiscal stimulus, at 3.5 per

cent of the GDP, at current market prices for 2008-09, amounts to Rs. 1,86,000 crores". The fact of the matter, as Mr. Venkaiah Naidu was also reading all those figures, which my good friend, Gurumurthy, has worked out, is that of this figure, two-thirds, that is, Rs. 1,30,000 crores have nothing to do with the stimulus at all.

It is fallen tax collections because of the slow down; it is the Sixth Pay Commission dues; it is the fertilizer subsidy; it is the food subsidy and it is the extra interest on borrowers. The same thing is about the stimulus that is being said for tomorrow.

We are now being told that this extra expenditure of Rs.1,20,000 crores is what is for the future. The fact is that of this Rs.1,20,000 crores, Rs.97,000 crores, as Shri Venkaiah Naidu also quoted, is because of the dues on account of the Sixth Pay Commission, extra interest of Rs.33,000 crores, Non-Plans, as you said now, about IMF contributions and so on. It is only Rs.42,000 crores which is an extra expenditure on the Plan. Now, Sir, I mentioned this because this is becoming a habit. In the February Interim Budget, we were told on behalf of the Government that one of the FRBM targets is being pushed ahead because of the global economic slow down. At that time, I had to read Shri P. Chidambaram's previous Budget in which he had said " Much before the global slow down we are pushing back this target because of social expenditure." So, this business of claiming credit for the things that are not getting done, which are not being reflected in the economy, is not a good thing. We may expect it of a lawyer like Shri Chidambaram but not from a seasoned man like Shri Pranab Mukherjee.

Sir, when we have Shri Rangarajan saying that we are getting into a vicious cycle in regard to the debt, I don't have to elaborate on that point, Sir. But the main point to remember in this regard, Sir, is that just 140 days ago, just that much time ago, Shri Pranab Mukherjee told us in the House that this deficit is going to be only 5.5 per cent of the GDP and, today, suddenly, it has become 6.8 per cent. No astronomical expenditure took place but it was just that you are giving bad news in those days. The net borrowing has risen four times higher this time than the Budget that was approved for 2008-09. That is the profligate way in which the finances of the country have been managed.

As Shri Rangarajan said, you will not only pre-empt private

borrowing, interest rates will just have to rise. We have been told by the Finance Minister that no, no, this will be done in a way in which rates will not rise. But there is no magic. He has held meetings with the Chairmen of the Banks, but if you read the Business Standards of today, you will find that all the Chairmen have said, 'Yes, interest rates will have to rise." As Shri Rangarajan just now said, when capital investment from the private sector comes up in a country in which household savings are 12 per cent of the GDP, when 11 per cent is taken up by the deficits of the Governments, then, how can there be a situation in which anything is left for the rest of the economy to grow? Sir, one point which should not be missed in regard to this deficit is how it is squeezing out any manoeuvreability for the future. I think we don't quite recognize that. Sir, if you take only debt servicing, it is already 94 per cent of the gross revenue receipts of the Government. About 94 per cent of the gross revenue receipts are eaten up only in paying interest on past debt and on repaying that debt. If you take net revenue receipts of the Centre, then, just that debt servicing is 120 per cent of that net revenue receipts of the Government. If we take unavoidable expenditure only, interest payment, subsidies, pension, salaries, revenue expenditure on Defence, revenue expenditure on Police, repayment of debt, that is 55 per cent more than the gross revenue receipts of the Government. It is twice the net revenue receipts of the Centre. That is the squeeze in which we have got in. And, our only answer to that is, to increase borrowing this time by Rs.3,97,000 crores.

How is this going to be sustained?

So, the point that NK was making on sustainability is really to be seen in the context that how we are just completely squeezing out not just the private sector and all, but the manoeuvrability and options of the Government of India itself. And, Sir, these figures are only the Revised Estimates. When the final figures come for the year, you will see it will be much greater.

Sir, on specific programmes, on disinvestment and all, I don't really want to take your time. I had a good occasion to speak on this in the President's Address, but, Sir, I would like to touch only one point, i.e., in regard to paragraphs 53 and 54. And, I will request Members to please bear with me because it is a sensitive matter.

As I mentioned earlier, like everybody in this House I am for all positive help to every section of society, namely, Schedule Castes, Muslims, Christians, Hindus, anybody irrespective. I had spelt out five secular principles on which such assistance should be given. It should be based on the individual, not a group. Second, in identifying that individual, use secular criteria, as you do in APLèBPL.

Sir, when the assistance is given, the criteria on which it is given, discourse congeals around it, politics congeals around it, power congeals around it and it has great consequences. On the question of caste itself, it is a curse and it was being eroded by modernisation and electoral politics; and such schemes of Government and reservations based on caste, etc., have fortified it to a dangerous extent. So, the point is, when you give assistance, please don't give it on a criterion which widens the earth fault lines in our society. Sir, I want to read to you just one passage from a book written in 1940s and you will see that this warning will come true again, unfortunately, within our short life times that remain for us because of this politics which is being pursued, a vote bank politics, either on caste or religion or so on, and that is what is reflected in these paragraphs 53, 54 that I mentioned.

Sir, it is one of the great scholars on comparative religions, a man called W. Cantwell Smith who wrote in the 1940s about India and what was happening. Unfortunately, his prophecy regarding the partition of India came true. But in this particular chapter, he is recounting evolution of British Policy and he said that the essence of British policy was to offer a boon which a group could claim only if and only to the extent to which it remained different from the rest of the society; and he says, "The Government's method of encouraging communalism has been to approach all political subjects, and as many other subjects as possible, on a communalist basis; and to encourage, even to insist upon, everyone else's doing likewise. The principal technique is separate electorates: making the enfranchised -- Muslims in that case -- and the enfranchised sections of many other groups, into an increasing number of separate constituencies, so that they vote communally, think communally, listen only to communal election speeches, judge the delegates communally, look for constitutional and other reforms only in terms of more relative communal power and express their grievances

communally. Even the British Government has admitted on occasions that the system serves to keep India from gaining independence by political means." And, just see, Sir, he quotes the Secretary of State, Edwin Montague who says, "Division by creeds and classes means the creation of political camps organised against each other, and teaches men to think as partisans and not as citizens."

We regard any system of communal electorate, therefore, as a very serious hindrance to the development of a self-governing principle". Therefore, we are encouraging it. And, as the same statement says, "The principle works so well that once it has been firmly established, it so entrenches communalism that one could then hardly abandon the principle even if one wished to do so". This is what I had in mind when I pleaded with the Prime Minister to think again on these allocations and instructions which had gone from his own office to the banks to keep ledgers on how many loans had been given by religion.

Sir, I do not wish to end on a combative note. I would, Sir, in seven sentences, give seven suggestions to the Finance Minister in view of what I have said and what very learned people like Shri Rangarajan, Shri N.K. Singh and many other friends have said. First, please, implement your resolve to get back to the discipline of the FRBM; do not listen to the economics of lawyers like Mr. Abhishek Singhvi. As Mr. Rangarajan said, to restore confidence in this, it is not necessary only to give specific steps, it is also necessary to lay out a roadmap. And as every Member who has spoken on this matter in regard to the medium term document that is given here has rightly remarked, it is just not a sufficiently detailed thing to invite any confidence in this regard. Second, in particular, please, reign in current expenditure. In this it requires the cooperation of the whole House because if all of us keep pressing sectional demands, then no Finance Minister will be able to discipline the expenditure. Third, for this purpose, please examine closely what is being done in the name of inclusiveness. This is just becoming a mantra; you paste this label and do anything that you like! Fourth, for this purpose, please, take people into confidence. You are not disclosing either the true economic situation or the measures that are required.

Then, please expedite implementation of projects. Ensure effective implementation. This will require more than committees.

Two days ago, there was a big headline saying that the Prime Minister is now going to chair a thirteen-member committee to expedite infrastructure projects.

But the Prime Minister already chairs a committee to expedite infrastructure projects! There is a committee already! It is the same committee; now two new members have been named. We are now being told, and it is a big headline. So, it will require more than this purpose. The second last is: resume reforms; finally, a new architecture in all this. For all these purposes and all the important issues that I have mentioned in the beginning in regard to standing up to pressure, I wish the MoS will convey to the Minister of Finance my great hope in him and we wish him strength within Government and luck outside the Government. Thank you, Sir.

सारांश

जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही थी तो मैंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि चीन ने अरूणाचल प्रदेश से संबंधित एशियाई विकास बैंक से भारत के ऋण को रोक दिया था। यद्यपि यह ऋण लगभग चार बिलियन डालर का था। भारत ने इस संबंध में एक स्पष्ट और कड़ा रूख अपनाया था। इसने अमरीका सहित अन्य देशों का समर्थन जुटाया और इसका परिणाम यह हुआ कि बोर्ड ने निर्णय किया कि भारत को ऋण दिया जाए। यह पहली बार हुआ कि चीन को धक्का लगा।

हम सभी समझते हैं कि बजट कठिन परिस्थितियों में तैयार किया जाता है और सन्तुलित कार्य करना होता है। सुधारों के रूकने की वजह से रफ्तार धीमी हो गई थी। फ्रिंज लाभ समाप्त कर दिए गए हैं। यह अच्छी बात है कि वस्तु लेन देन कर को, जो वास्तव में ही कभी लागू ही नहीं किया गया था, समाप्त कर दिया गया है। जी. एस. टी. अधूरा अथवा खराब तरीके से नहीं बनाया जाना चाहिए। इन मामलों पर देश में विचार करने के लिए, यहां तक कि सहमति बनाने के लिए एक वर्ष अधिक समय है। इसमें अनेक विशेष उपाय है जो मुझे सराहनीय लगे। अवसंरचना वित्त आयोग के लिए जिस सहायता की घोषणा की जा रही है, वह भी एक अच्छी बात है। यह एक ऐसी संरचना, दूर दृष्टि है जिसकी विशेष रूप से ऐसे समय में आवश्यकता है जब देश को लग रहा है कि वह मुसीबतों में है। इसे इस संबंध में एक

सामान्य आर्थिक नीति और सुधारों के संबंध में एक 'रोड मैप' की आवश्यकता है।

मैं सदस्यों से राजसहायता के मुद्दे पर सरकार की सहायता करने के लिए एकमत तैयार करने का अनुरोध करता हूँ। मैं सशक्त निजी क्षेत्र, सशक्त और कुशल सरकार, सशक्त सरकारी क्षेत्र का समर्थक हूँ ताकि आपके यहां प्रतिस्पर्धा हो और मूल्य नीचे आ जाएं तथा कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाए। आर्थिक युक्तिसंगतता यह सुझाती है कि आयात तुल्यता के स्थान पर मूल्य निर्धारण के लिए व्यापार तुल्यता होनी चाहिए। आपके यहां राजनीतिक दलों अथवा बाहरी लोगों के भीतर मात्र गतिहीनता ही नहीं है बल्कि आपके अन्य हित युक्तिसंगत नीतियों के आड़े आ रहे हैं। दूसरा सुधार उर्वरक संबंधी राजसहायता संबंधी है। हम केवल नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान करते हैं और यह फॉस्फेटों, पोटाशों संबंधी उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन का कारण बनता है तथा यह हमारी धरती के ह्रास का कारण बन रहा है। हमें आज यह बताया जा रहा है कि अंततः हम पोषण आधारित राजसहायता व्यवस्था की ओर बढ रहे हैं। यूरिया पर राजसहायता जारी रखना जबकि पीएनके उर्वरकों को मूल्य नियंत्रण से मुक्त करने से उर्वरकों के इस्तेमाल में असंतुलन को अनभिप्रेत रूप से अधिक बढ़ावा मिलता है। श्री चिदम्बरम ने 2007–08 के अपने बजट में पहले कहा कि यह एक गंभीर समस्या है। जबकि उर्वरकों पर वास्तव में राजसहायता मिलनी चाहिए लेकिन हमें किसानों को राजसहायता प्रदान करने का वैकल्पिक तरीका ढूंढना चाहिए। यही बात हूबहु वर्तमान वित्त मंत्री जी ने कही है। तथ्य यह है कि वही वायदे लगातार किए जाते हैं और लागू नहीं किए जाते हैं जो इस तथ्य को दर्शाता है कि हम उस ओर नहीं बढ रहे हैं जिस ओर हमें बढना चाहिए। 15 से 20 वर्षों में और निश्चित रूप से पिछले पांच वर्षों में मात्र इसी बात को दोहराया गया है।

आपके आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इसके अलावा, पोषण आधारित राजसहातया मूल्य निर्धारण के कार्यान्वयन के कारण विभिन्न जटिल उर्वरकों के मूल्य औसतन 18 प्रतिशत कम हो गये थे। सरकार ने उर्वरक क्षेत्र के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें आरंभ की है। पीओएल के संबंध में केवल दो सुधारों का उल्लेख किया गया है, उनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। मंत्रालय का एक हिस्सा यह नहीं जानता कि उसका दूसरा हिस्सा क्या कर रहा है। विद्युत के संबंध में समस्या यह है कि हमने ग्यारहवीं योजना के

लिए 78 हजार मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमने अब तक केवल 13 हजार मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त किया है। निधियों की कमी के कारण हम इस वर्ष 40 हजार अतिरिक्त मेगावाट तक प्राप्त नहीं कर करेंगे। श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम विद्युत, मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने हेतु महत्वपूर्ण है। मैं इस योजना के लि आवंटन में 2080 करोड़ रूप की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखता हूं जो सीधे 160 प्रतिशत की वृद्धि है।

उस निधि के बारे में क्या हुआ जो आने वाली थी। मामले पर इस समय जांच चल रही है और जो चलती रहेगी। समय–समय पर किए गए वायदों पर निगरानी रखने का यही कारण है। इसे उपलब्धि के रूप में दर्शाया जाता है। वास्तव में यही संस्कृति रोजगार योजनाओं और हर चीज के संबंध में जारी है। एक बार हमें इस सभा में बताया गया था कि मंत्रालयों को आउटकम बजट बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। मुझे नहीं मालूम की उसका क्या हुआ। 2009–10 के बजट संबंधी पत्रों की सूची में 13 विषय हैं। लेकिन एक विषय गायब था। यह बजट घोषणा का कार्यान्वयन है। क्या वह पत्र परेशानी सिद्ध हो रहा था क्योंकि हममें से कुछ लोग उसे पढते थे? खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधी इस महत्वपूर्ण वायदे के संबंध में भी यही बात है। हम मात्र संकल्प पारित करते जाते हैं, ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते जाते हैं। वास्तविक समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 316 मिलियन लोगों को शामिल किए जाने के बावजूद हम ग्लोबल हंगर सूचकांक में 66वें स्थान पर हैं। यहां तक कि विफल देश भी हमारे से ऊपर है। अधिक से अधिक विधान पारित करने के स्थान पर हमें वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे मामलों पर ध्यान देना चाहिए। घाटे के मुद्दे पर बजट में कहा गया है कि, 'अर्थव्यवस्था में वैश्विक मंदी के नकारात्मक नतीजे का सामना करने के लिए हमने यह घाटे की व्यवस्था की है'। 2007–08 और 2008–09 की वास्तविक बजट राशियों के बीच का अंतर कुल वित्तीय प्रोत्साहन बन गया है, जो 1,86,000 करोड़ रुपए के बराबर है। इसमें से 1,30,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन के साथ बिल्कुल संबंध नहीं है। केवल 42,000 करोड़ के योजना संबंधी अतिरिक्त व्यय है। वे बातें, जो नहीं कराई जाती है और जिन्हें अर्थव्यवस्था में नहीं दर्शाया जाता है, के लिए श्रेय लेने का कार्य अच्छी बात नहीं है। जहां तक ऋण का संबंध है, सकल ऋणों में 2008–09 के लिए संस्वीकृत हुए बजट

की तुलना में 4 गुणा वृद्धि हो गयी है। यह अपव्ययी तरीका है जिससे देश के वित्त की व्यवस्था की गयी है। यह घाटा भविष्य के लिए युक्ति से काम लेने की क्षमता को कम कर रहा है। यदि आप केवल ऋण अदायगी को लें तो यह पहले से ही सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियों का 94 प्रतिशत है।

इस सभा में सभी की तरह मैं भी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सकारात्मक सहायता का पक्षधर हूँ। परंतु यह किसी समूह पर आधारित न होकर व्यक्ति पर आधारित होनी चाहिए। व्यक्ति की पहचान करते हुए धर्म निरपेक्ष मानदंडों का प्रयोग करें जैसे कि आपने एपीएल/बीपीएल के मामले में किया। जो राजनीति की जा रही है, वोट बैंक की राजनीति चाहे वह जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, उसके कारण समाज को और नुकसान पहुँचेगा।

मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि वह इन आवंटनों और निर्देशों के बारे में पुनः विचार करें जो उनके कार्यालय से बैंकों को दिये गये थे कि ऋण देते हुए इसका हिसाब रखा जाए कि यह किस–किस धर्म के लोगों को दिये गये हैं। जो मैंने कहा, उसके दृष्टिगत मैं वित्त मंत्री को सात सुझाव दूंगा। कृपया राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन में अनुशासन रखने का अपना संकल्प कार्यान्वित करें। अपने वर्तमान व्ययों पर अंकुश लगाएं। इसके लिए पूरी सभा के सहयोग की जरूरत है क्योंकि यदि हम सभी क्षेत्रीय मांगों के लिए दबाव डालेंगे तो कोई भी वित्त मंत्री व्यय को नियंत्रित नहीं कर पायेगा। इस बात की गहनता से जांच करें जो समवेशी के नाम पर किया जा रहा है। लोगों को विश्वास में लें। आप सही आर्थिक स्थिति या इसके लिए जरूरी उपायों का खुलासा नहीं कर रहे हैं। परियोजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्रता से करें। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। इसके लिए केवल समितियां गठित करने से भी काम नहीं चलेगा। अर्थव्यवस्था में सुधार करें और अन्त में इन सभी के लिए नई रूपरेखा तैयार करें।

India in a debt-trap

— N. K. Singh

Thank you, Mr. Vice-Chairman Sir. Let me get back into fashion. The fashionable thing these days is Kautilya and let me begin by, therefore, quoting one little stuff from Kautilya which the Finance Minister perhaps should have known. Kautilya said, 'That a king with a depleted treasury will eat into the vitals of its citizens and the common people'. Obviously, Kautilya was not a mere economist, but perhaps, an astrologer to have known the configurations of Indian finances of 14th June, 2010. It is not as if that the Finance Minister who is no novice to the world of finance haven't done a credible job in balancing several asymmetries in perhaps seeking relaxation from fiscal rectitude to fostering growth, forgetting inflation, reviving consumption, putting money into infrastructure, rural development with a view to try and get back the country into a higher growth trajectory. In this balancing act, which is quite credible, there are several important factors which I thought he has overlooked. First and foremost is the issue of sustainability. I don't want to go more into this but the raw fact remains that a 6.8 per cent fiscal deficit of the Central Government when added to a four per cent deficit of a State and add it to under-recoveries of 30,000 crores on current prices of petroleum with a likelihood of prices going up and with a lot of under provisioning on account of things which will happen, the fiscal deficit will turn out to be close to 12-13 per cent of the GDP.

This alone entails a Rs. 4,00,000 crores of borrowing. The explanation that Rs. 2,00,000 crore may come out in the open market borrowed operations of the Reserve Bank is, perhaps, a fiction because, we know that an open market operation of this nature is neither possible nor feasible, and that the only ultimate outcome would be a substantial monetisation of the fiscal deficit and, that, Sir, embeds the system with deep inflationary pressures. So, there are inherent serious concerns on the macro fundamentals of the economy.

In fact, the hon. Finance Minister goes on, perhaps, recognise this a little later, but not before he has gone to another fiction. That intermediate fiction is a document which he has placed along with the Budget entitled 'Medium Term Fiscal Policy Statement.' What does that Policy Statement say, Sir? It says that next year and the year after, the fiscal deficit, including the revenue deficit, would undergo a correction of 3 percentage points. There are no expenditure plans. Or, what expenditure plans would be rolled back? There are no additional revenue realisations. The expectation of corporate revenues going up by 15 per cent, with income tax revenues going down by 6 per cent, is something which totally lacks credibility. In fact, the only truthful part of the Medium Term Fiscal Policy Statement is the concluding part of that statement. What does that conclusion says? With your permission, Sir, I read it. The last sentence of the Fiscal Policy Statement says and I quote, "Without putting at risk the revival process, the Government will look at exit strategies as soon as there is an improvement in the economic condition." This is a more realistic statement, because here they return to the path of fiscal rectitude. It is an open-ended one. Therefore, this is in sharp contrast to what he has said earlier, namely put definite numbers on what he intends to do next year and what he intends to thereafter. My second important issue and quarrel with the Budget is this. Does the Budget address the fundamental issue that this is the right strategy for reverse in the decline in the growth rate? Independent international studies have shown that the Indian economy had peaked in 2006-07. If you look at really the third quarter statement of the year 2006-07, the GDP growth has climbed up to 9.6 per cent. The manufacturing sector has climbed up to

12.2 per cent. For every successive quarter, after the third quarter of 2006-07, there comes a decline till you come to the last quarter of 2008-09 when the GDP growths have collapsed and the manufacturing sector is down in the negative. The point I am trying to make is that the decline of the Indian economy, the GDP growth and the manufacturing sector began much before the global crisis had hit us. Therefore, to really put the Indian economic situation contingent on the exogenous variable of a looming global crisis is misleading us. We, therefore, need to ask ourselves a question that, perhaps, the economy has run out of steam. Perhaps, we need endemic solutions. Perhaps, there are institutional bottlenecks. Perhaps, there are infrastructural bottlenecks. And, till, therefore, these begin to get addressed, this kind of an artificial fiscal stimulus package will only bring a temporary reprieve, because it will not address the more fundamental endemic causes which led to the decline of the Indian economy one year before the beginning of the global economic crisis.

My third point is about the quality of stimulus. Sir, out of 120,000 crores extra which has been put into the system, Rs. 44,000 crores go to the Pay Commission, Rs. 33,000 crores goes to the interest payments, Rs. 10,000 crores goes to contribution to the International Monetary Fund. In fact, the real increase in areas on which Government claims a lot of credit for is a miniscule about. If you combine, for instance, the NAREGA increase with the Grameen Rozgar Yojna, the increase is 0.7 per cent. The SSA programme, the primary flagship programme on education, there is a decline. In rural development, the increase is only 0.38 per cent. On child welfare the increase is awfully 0.8 per cent. In fact, the most of the increases have gone on into boosting consumption, not gone into capital creating assets and not gone into those investments which will have long-term multiplier effects to the Indian economy. Therefore, first and foremost, the increases are nominal and they have gone into directions which may not leave a permanent impact on the economy.

My forth point is that a lot of credit has been taken by the hon. Finance Minister for the introduction of GST from 1st April, 2010. I recognise this is an important step. But, perhaps, the Constitutional

legal changes which are necessary and the kind of harmonisation of many deficiencies between different States and the consensus building in the political process is really running behind time and we only hope and wish that he is able to do so. Let me tell this that nothing would be more terrible than to hastily introduce an ill-conceived GST, because that is only enhances the distortory tax structure. It is better to plan and introduce more carefully.

My fifth point is this. Nothing has been done to improve the overall climate for private investment. In fact, the one, on Integrated Energy Policy, again, is flawed because we have tinkered with the policy. We have not tried to own our past contractual liability. We have suddenly changed regimes without giving a proper notice. We have detracted from credibility and from investors' confidence. So, Sir, the short point is, India is in a debt-trap. At today's debt numbers of roughly 87 per cent of the GDP, the Government owes every Indian Rs. 45,050è-. In 2011 and 2012, the Government would owe every Indian Rs. 67,375è-. Look at the kind of miniscule tax breaks.

Look at the kind of woeful debt, which the Government has created. In fact, one can only end up by saying that all that the Finance Minister wishes to say, in his fiscal policy statement, is, "Oh Lord! Make me prudent. But wait for it, not now." And, in fact, he does not end up by saying, "Blessed we be to the newer generation because thou shall inherit my debt". So, what is really the path forward? I would like to say, for the submission of the Government, ten very quick suggestions. First and foremost, make greater fiscal zoom to allow States half-a-percentage point more and reduce the fiscal deficit of the Central Government by half percentage point to keep the equilibrium going. Second, stop cherry picking and have a more equal treatment. I have no problems with giving cherry-picking to West Bengal, to Maharashtra and to other parts of the country. But do so equally, in an even-handed way to the other parts of the country, following the cardinal principle of fiscal federalism in which we play a political neutrality in devolution of funds and in being able to start and initiate development projects. Third, come up with a more credible detailed White Paper on returning to the path of fiscal rectitude, with a better outlined path of fiscal consolidation, not by mere rhetoric, but with stiffening of

political spine, which comes up with a credible action plan. Fourth, the Finance Minister, on page 40 of his Fiscal Responsibility Programme, has come up with an excellent suggestion to set up an Independent Evaluation Office to go into public outlays. Set up this office as soon as possible since so much faith has been placed in public outlays.

Fifth, create an office of public debt to begin to obviate the conflict of interests, which the Reserve Bank has, since the Government has an enormous portfolio in the management of public debt. Sixth, restructure the Reserve Bank of India by creating a separate banking supervisory authority to again obviate the conflict of interests in the Reserve Bank, managing two kinds of areas where there is an inherent conflict. Seventh, based on the President's Joint Address, urge the Ministries to come up with individual papers on what their action programme is and how they intend to take forward the many ideas embedded in the Finance Minister's speech. Eight, Mahalanobis, I am sure Brindaji will agree, was no reactionary. Writing fifty years ago, he talked about the need that in the constitutional scheme of things, fiscal federalism, in a new polity, needed to be revisited to give India a comparative advantage of a large labour force to be able to create employment outside agriculture and seek livelihood in labour-intensive manufacturing activity. Ninth, come up with a medium-term programme in the legislative domain, not merely in the area of what people describe as neo-liberal economics, but in other areas, like, in health, in education, in Judiciary to be able to have a kind of growth, which is sustainable, which is truly creative, and which is inclusive. Finally, Sir, let me say that this Government has come back to power by making huge promises. People remember these promises. Therefore, begin to perform in a credible way because, surely, you will remember that the memory of creditors is far more than the memory of debtors.

Thank you, Sir.

सारांश

यद्यपि, वित्त मंत्री ने अनेक विषम–विषयों में संतुलन कायम करने हेतु एक विश्वसनीय कार्य करने का प्रयास किया है तथापि, मेरे विचार से, इस संतुलन के प्रयास में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कारकों की अनदेखी की है। सर्वप्रथम मुद्दा है– निरंतरता। कटु सत्य यही है कि केन्द्रीय सरकार के 6.8 प्रतिशत राजकोषीय घाटे में यदि किसी राज्य के 4 प्रतिशत घाटे को जोड़ दिया जाए और फिर उसमें पेट्रोलियम की वर्तमान कीमतों, जिनमें और वृद्धि होने की संभावना है, की 30,000 करोड़ रुपए की कम प्राप्त हुई राशि को जोड़ दिया जाए और इसी प्रकार से अन्य बातों को भी जोड़ दिया जाए तो सकल राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद कालगभग 12–13 प्रतिशत बैठेगा। अंततोगत्वा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फ्रीति का गहन दबाव बढेगा। इसके समाधान के रूप में वित्त मंत्री महोदय ने 'मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण' प्रदान किया है जिसमें कहा गया है कि अगले वर्ष और उससे अगले वर्ष राजस्व घाटे सहित राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत का सुधार कर लेगा। चूँकि राजस्व प्राप्ति के कोई अतिरिक्त स्रोत नहीं है इसलिए यह एक कल्पना ही प्रतीत होती है। विभिन्न स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन यह दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2006–07 में अपने शिखर पर थी। अब, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर चरमरा गयी है और विनिर्माण क्षेत्र में भी नकारात्मक वृद्धि हो रही है। संभवतः, अर्थव्यवस्था कुंद हो गयी है। किसी प्रकार का बनावटी राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज केवल अस्थायी राहत प्रदान कर सकता है। यदि हम वेतन आयोग, ब्याज भुगतान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को प्रदान किए जाने वाले अंश को इस प्रोत्साहन पैकेज में से निकाल दें इस प्रोत्साहन की गुणवत्ता अति न्यून सिद्ध होती है। जिसके परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था पर इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1 अप्रैल, 2010 से सामान्य बिक्री कर की शुरूआत किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। किंतु, इसे बेहतर योजना तथा अधिक सावधानी से लागू किया जाना चाहिए। गैर–सरकारी निवेश के लिए संपूर्ण परिवेश में सुधार के लिए कुछ नहीं किया गया है। आज, भारत ऋण के जाल में उलझा हुआ है। आज, सरकार पर प्रत्येक भारतीय के लिए 45050 रुपए का कर्ज है। 2011 और 2012 में, सरकार पर प्रत्येक भारतीय के 67375 रुपए का कर्ज होगा।

मेरे निम्नलिखित दस त्वरित सुझाव हैं। केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय

घाटे को कम करने के लिए राज्यों को आधा प्रतिशत अधिक राशि वहन करने को मंजूरी दी जाए। सभी राज्यों को निधियों का समान अंश प्रदान किया जाए। राजकोषीय सुधार के लिए एक विश्वसनीय कार्य योजना पेश की जाए। सार्वजनिक परिव्ययों की बारीकी से छानबीन के लिए यथाशीघ्र एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय स्थापित किया जाए। एक सार्वजनिक विभाग कार्यालय का सृजन किया जाए। एक पृथक बैंकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकरण का सृजन किया जाए। मंत्रियों से अपने–अपने कार्यक्रमों से संबंधित व्यक्तिगत प्रपत्र प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाए। श्रमबहुल विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि की जाए। स्वास्थ्य, न्यायपालिका इत्यादि जैसे क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करने के लिए मध्यम अवधि के कार्यक्रम तैयार किए जाए जिससे सतत, सृजनात्मक और समावेशी विकास किया जा सके और अंततः, चुनावों के दौरान जनता से किए गए सभी वायदे पूरे किए जाए।